PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 326 ● भिलाई, शनिवार 11 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

गर्ल्स हॉस्टल में जहरीले सांप का कहर, रात में सोते समय 4 छात्राओं को डसा

लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय एक जहरीला करैत सांप घुस आया और गहरी नींद में सो रही 4 मासूम छात्राओं को अपना शिकार बना लिया। इस आसमानी आफत में 13 साल की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य छात्राओं की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस हृदयविदारक घटना से स्कूल परिसर और छात्राओं के परिजनों में भारी चीख-पुकार और कोहराम मच गया है। अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक घटना मंगलवार रात रोचो महुआटोली स्थित सनवसिरा हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल में हुई। रोजाना की तरह सभी छात्राएं रात का खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चली गई थीं। रात करीब 11 बजे, जब सभी बच्चियां गहरी नींद में थीं, तभी एक अत्यधिक जहरीला करैत सांप रात के अंधेरे में चुपके से उनके कमरे में घुस गया।

महाराष्ट्र के पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, कलेक्टर ने जारी की सख्त चेतावनी

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग होने के साथ ही डर के साये में जी रहा है. रायगढ़ में भारी बारिश के कारण पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3,000 भरे और खाली गैस सिलेंडर नदी में बह गए, वहीं, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उन्हें नदी में गैस सिलेंडर दिखाई दें तो प्रशासन को सूचना दें. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है. रायगढ़ के पनवेल में भारी बारिश के कारण बॉटलिंग प्लांट में पानी भरने से करीब 3,000 एलपीजी सिलेंडर पातालगंगा नदी में बह गए, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

टायर फटते ही धधक उठी बस, इंदौर में समय रहते बची यात्रियों की जान

इन्दौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां रीवा से इंदौर आ रही एक यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। यह दर्दनाक हादसा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे शिप्रा थाना क्षेत्र के ठीक सामने घटित हुआ। गनीमत यह रही कि आग की लपटें विकराल रूप लेतीं, उससे पहले ही बस में सवार सभी यात्रियों को सूझबूझ के साथ समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शिप्रा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जय अंबे ट्रेवल्स की यह बस जब थाने के सामने से गुजर रही थी।

बांकीपुर में बीजेपी ने झटपट बदल दिया कैंडिडेट

अभिषेक कुमार सिन्हा ने छोड़ा,अब नीरज सिन्हा लड़ेंगे चुनाव

बांकीपुर/ एजेंसी

बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया है और अब नीरज सिन्हा बांकीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद शुक्रवार को नए उम्मीदवार की घोषणा की गई है, इसके बाद नीरज कुमार सिन्हा का नाम लाइम लाइट में आया। भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद नीरज सिन्हा पार्टी दफ्तर पहुंचे और आभार जताया है। नीरज कुमार सिन्हा ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है और अभी वे अविवाहित हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली थी और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। संगठन में उन्होंने बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और वर्तमान में लगातार दूसरी बार नरेंद्र भारती मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके चाचा स्वर्गीय नरेंद्र भारती जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनकी स्मृति में ही मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया है। अभिषेक सिन्हा बंटी के नाम वापस लेने के बाद भाजपा ने बिना समय गंवाए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार इसलिए बनाया क्योंकि वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। बांकीपुर सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और यह भाजपा के लिए अभेद्य गढ़ कही जाती है। बता दें कि इस सीट से साल 1995 से बीजेपी को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। इस तरह से नीरज कुमार सिन्हा पर पार्टी को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी है। बता दें कि बांकीपुर सीट से राजद ने रेखा देवी को उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट से पहली बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा देवी और जनसुराज के प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावना है। पटना के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार 'बंटी' को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पार्टी ने बांकीपुर सीट से पूर्व विधायक एवं वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी माने जाने वाले अभिषेक कुमार बंटी पर दांव लगाकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था, लेकिन अब उन्होंने नामांकन ही वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने इस चुनाव में कायस्थ मतदाताओं के साथ-साथ पारंपरिक भाजपा वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई थी।

आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने बनाया दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार

भोपाल: मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी के नाम पर अपनी स्वीकृति दी है। आशुतोष जल्द ही अपना नामांकन फाइल करेंगे। इससे पहले माना जा रहा है आशुतोष तिवारी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और वह आरएसएस के पूर्व सभागीय संगठन मंत्री रहे हैं। आशुतोष एमपी माइनिंग बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को दतिया की खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी।

ऑपरेशन तुतारी' की तैयारी

एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर चर्चा गर्म

नई दिल्ली/ एजेंसी

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. 'ऑपरेशन टाइगर' के बाद अब 'ऑपरेशन तुतारी' की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है. महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद और अजित पवार गुटों के संभावित विलय की चर्चाएं तेज हो गयी हैं. भविष्य के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के बीच फिर से एकजुट होने की कोशिशें तेज हो गई हैं. कयास यह लगाया जा रहा है कि प्रतिद्वंद्वी एनसीपी गुटों के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने से पहले विलय होने की संभावना है. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और अजित पवार गुटों के विलय या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की चर्चाएं भूर जोर से जोर पकड़ी हुई है.

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ।

इजरायल के खुफिया दावे से हड़कंप

ट्रंप को मारने का प्लान बना चुका है ईरान !

नई दिल्ली/ एजेंसी

अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इजरायल ने अमेरिका के साथ साझा की गई एक नई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इनपुट ने वॉशिंगटन की सुरक्षा एजेंसियों और नीति-निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह नई खुफिया जानकारी ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति और संभावित परमाणु समझौते को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है ।

हाई कोर्ट ने बरकरार रखी सजा, पैसे देने से मुकरे एक्टर

अभिनेता राजपाल यादव फिर जाएंगे तीन महीने के लिए जेल

नई दिल्ली/ एजेंसी

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर कुल 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार, 10 जुलाई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सातों मामलों में अलग-अलग तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है। हालांकि, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका मतलब है कि राजपाल यादव को कुल तीन महीने की ही जेल काटनी होगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने बार-बार मौका मिलने के बावजूद शर्तों का पालन नहीं किया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस हिसाब से सात मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे। यह मामला साल 2010 में रिलीज हुई राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी।

महाराष्ट्र-गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, एमपी में गिरी 5 मंजिला इमारत, राजस्थान की सड़कें बनीं दरिया

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई स्थानों पर यातायात पूरी तरह बाधित है। महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में दो गांवों को जोड़ने वाला पुल और सड़क तेज बहाव में बह गए हैं।

दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं शेख हसीना

गिरफ्तार करें या मार दें,अपनी मिट्टी पर मरना चाहती हूं-शेख

नई दिल्ली/ एजेंसी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और आवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने संकेत दिया है कि वह इस वर्ष दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वापसी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने देश लौटने का फैसला कर चुकी हैं। हसीना ने कहा, हो सकता है कि लौटते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या मुझे मार दिया जाए, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर मौत आती है तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी धरती पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था। दिल्ली में निर्वासन के दौरान रह रहीं हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत सरकार को उन्हें वापस भेजने के लिए पत्र लिख रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विदेशी सरकार से अपनी वापसी को लेकर कोई सलाह या समन्वय नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैं खुद लौटूंगी। हमारे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। कई लोग छिपे हुए हैं। हम सभी अदालत में जाकर आत्मसमर्पण करेंगे। शेख हसीना ने अपनी संभावित वापसी की सटीक तारीख बताने से इनकार किया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वह किस अदालत में आत्मसमर्पण करेंगी। उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और कानूनी प्रक्रिया के दौरान सच्चाई सामने आएगी।

कबीरधाम धान घोटाले में कसा शिकंजा

सोसायटी प्रबंधक के घर मारा रेड,16 लाखों कैश बरामद किए

कवर्धा। संवाददाता

कबीरधाम जिले में हुए कथित धान घोटाले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों से धान गायब होने के मामले में पुलिस ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज की है। जांच के तहत पुलिस लगातार आरोपियों के घरों और कार्यालयों में दबिश देकर अहम साक्ष्य जुटा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने लोहारा धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी गंगादास मानिकपुरी के घर और कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान पुलिस को 16 लाख रुपए नगद, बैंक पासबुक, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं कार्यालय में रखा कंप्यूटर मिला, जिन्हें जब्त कर जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धान घोटाले से जुड़े अन्य नामजद आरोपियों के घरों और कार्यालयों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। जिले में धान घोटाले को लेकर पुलिस की लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने लोहारा धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी गंगादास मानिकपुरी के निवास और कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस को लगभग 16 लाख रुपये नकद, बैंक पासबुक, कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज मिले. पुलिस ने सभी सामग्री को जब्त कर जांच में शामिल कर लिया है. अधिकारियों का मानना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड से मामले की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिले में लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से धान घोटाले से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है. जांच एजेंसियां वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की गहन पड़ताल कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं. कबीरधाम एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि धान घोटाले की जांच पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है. इस मामले में नामजद सभी आरोपियों के घरों और कार्यालयों में आवश्यकतानुसार तलाशी की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें तीन मामले अकेले लोहारा के हैं. आज लोहारा धान उपार्जन केंद्र प्रभारी के घर पर

महासमुंद में 17.93 करोड़ रुपये का धान घोटाला, 15 समितियों पर एफआईआर

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में करीब 17.93 करोड़ रुपये का कथित धान घोटाला सामने आया है। इस मामले ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में कई खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड में धान का स्टॉक दर्ज था। हालांकि, भौतिक सत्यापन के दौरान वहां स्टॉक नहीं मिला। वर्ष 2025-26 के धान खरीदी सत्र में 182 खरीदी केंद्रों से 1,01,95,681.20 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मिलिंग के बाद रिकॉर्ड के अनुसार 57,860.47 क्विंटल धान शेष होना चाहिए था। लेकिन, जांच के दौरान 54 केंद्रों पर यह स्टॉक नहीं मिला। गायब धान का मूल्य करीब 17 करोड़ 93 लाख 67 हजार 457 रुपये आंका गया है। यह समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर है। आरंगी और बम्हनी सहकारी समितियों में सबसे अधिक धान गायब मिला।

एसईसीएल की पांच खदानों को मिला 5-स्टार दर्जा, उत्कृष्ट खनन का राष्ट्रीय सम्मान

बंगवार, खैराहा, बेहराबांध, विजय वेस्ट एवं जगन्नाथपुर परियोजना को कोयला मंत्रालय की प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग

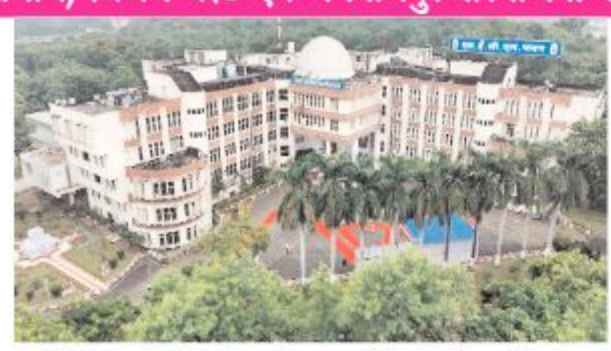

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने उत्कृष्ट एवं उत्तरदायी खनन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग में अपनी पाँच खदानों को 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है। बंगवार भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), खैराहा भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), बेहराबांध भूमिगत खदान (जोहिला क्षेत्र), विजय वेस्ट भूमिगत खदान (हसदेव क्षेत्र) तथा जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना (भटगांव क्षेत्र) को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। किसी एक मूल्यांकन वर्ष में एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। कोयला मंत्रालय की स्टार रेटिंग प्रणाली देश की कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसके अंतर्गत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण, भूमि पुनर्वास, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण, वैधानिक अनुपालन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परिचालन दक्षता जैसे विभिन्न मानकों पर खदानों का आकलन किया जाता है। इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानों को ही सर्वोच्च 5-स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है। इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की बंगवार, खैराहा, बेहराबांध एवं विजय वेस्ट भूमिगत खदानों ने सुरक्षित संचालन, वैज्ञानिक खनन, उत्पादन दक्षता, श्रमिक कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना, जो इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की एकमात्र ओपनकास्ट परियोजना है, ने ओवरबर्डन प्रबंधन, हरित विकास, जल संरक्षण एवं सुरक्षित उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। इस उपलब्धि पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने कहा- एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना पूरे एसईसीएल परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यावसायिक सहयोगियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है। सुरक्षित, सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल खनन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। आधुनिक तकनीकों और श्रेष्ठ खनन पद्धतियों को अपनाते हुए हम परिचालन उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। यह सम्मान हमें भविष्य में भी जिम्मेदार एवं सतत खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। एसईसीएल की यह उपलब्धि न केवल कंपनी की परिचालन दक्षता और सुरक्षा संस्कृति को रेखांकित करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और उत्तरदायी खनन के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। कोल इंडिया लिमिटेड की अग्रणी अनुषंगी कंपनी के रूप में एसईसीएल आधुनिक तकनीक, नवाचार और श्रेष्ठ खनन प्रथाओं के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात, 2,803 हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 40.39 लाख रुपए

केशकाल। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, केशकाल ने वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन के 2,803 संग्राहकों के बैंक खातों में 40 लाख 39 हजार 891 रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, केशकाल वनमंडल अंतर्गत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियां केशकाल और खालेमुरखेड के संग्राहकों को Online MFP Collection and Payment System के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। समिति केशकाल के अंतर्गत संचालित 31 तेंदूपत्ता फड़ों के संग्राहकों के खातों में भी प्रोत्साहन राशि जमा कराई गई है। इस ऑनलाइन व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हुई है। राज्य शासन वन मंत्री केदार कश्यप की मंशानुसार तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं वनाश्रित परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में प्रोत्साहन राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का उचित लाभ समय पर मिल सके। केशकाल वनमंडलाधिकारी दिव्या गौतम ने बताया कि सरकार का उद्देश्य तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से वनाश्रित परिवारों को सीधे लाभ मिल रहा है और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है।

खेल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की पहली सीढ़ी : कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

धमतरी। जिले के स्कूलों में खेल गतिविधियों को और प्रभावी बनाने तथा व्यायाम शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में व्यायाम शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने सभी व्यायाम शिक्षकों से स्कूलों में संचालित खेल गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के कई व्यायाम शिक्षक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैंए जबकि कुछ शिक्षक केवल औसत प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर व्यायाम शिक्षकों की रुचि नहीं होने के कारण विद्यार्थी खेल गतिविधियों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि यदि युवा खेलों से जुड़ेंगे तो वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे। खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और लक्ष्य प्राप्ति की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने सभी व्यायाम शिक्षकों को सक्रिय होकर कार्य करने तथा सप्ताह में कम से कम दो से तीन दिन नियमित रूप से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने व्यायाम शिक्षकों से अपने.अपने विद्यालयों के प्रतिभावान खिलाड़ियों का लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें जिला, संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने को कहा। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को व्यायाम शिक्षकों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्कूलों में उपलब्ध खेल सामग्री एवं खेल मैदानों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने, खेल मैदानों के समतलीकरण तथा आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार हैं। खेलों से जुड़ने वाले युवा अनुशासित बनते हैं और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं। सभी व्यायाम शिक्षक पूरी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ विद्यालयों में नियमित खेल गतिविधियां संचालित करें। प्रत्येक विद्यालय से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाए। साथ ही बच्चों के लिए आवश्यक खेल सामग्री और बेहतर खेल मैदान उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीआईजी

बेमेतरा। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने साजा भ्रमण के दौरान स्थानीय विश्राम गृह में नगर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों के साथ मुलाकात चर्चा की गई। जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी बनाने,डायल-112 सेवा के प्रचार - प्रसार एवं आसूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया। मुलाकात चर्चा में डीआईजी रामकृष्ण साहू ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने थाना स्तर पर सतर्कता बढ़ाने, अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर में निवासरत सभी किरायेदारों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मकान मालिक अपने यहां रहने वाले किरायेदारों का पूरा विवरण, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित थाना में जमा कराएं। उन्होंने कहा कि किरायेदार सत्यापन कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इससे संदिग्ध एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की पहचान करने में पुलिस को सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को सत्यापन अभियान को विशेष अभियान के रूप में संचालित कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर की यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। डीआईजी रामकृष्ण साहू ने ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने, बाजार क्षेत्र में यातायात सुचारु बनाए रखने तथा आवश्यकता अनुसार यातायात पुलिस की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों की सुविधा भी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बाजार क्षेत्र में मोबाइल चोरी, पॉकेटमारी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए डीआईजी ने ऐसे अपराधों में संलिप्त असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने पर जोर दिया। डीआईजी रामकृष्ण साहू ने उपस्थित नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, दुर्घटना, झगड़ा अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल डायल-112 पर दें। उन्होंने कहा कि समय पर प्राप्त सूचना से पुलिस त्वरित कार्रवाई कर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकती है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं सहभागिता जितनी मजबूत होगी, कानून-व्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी। उन्होंने थाना स्तर पर पुलिसिंग व्यवस्था में और अधिक सुधार, अपराधों के त्वरित निराकरण, नियमित गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी तथा आम नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास और अधिक मजबूत हो। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण को लेकर अपने सुझाव भी दिए, जिन पर डीआईजी रामकृष्ण साहू ने गंभीरता से अमल करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष हिमांशु वर्मा, लाल शौर्य जीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीनारायण चांडक, मूलचंद शर्मा, राजू शर्मा, वीरू वर्मा, जनपद पंचायत साजा के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, पार्षद कमल ठाकुर, थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोंडे सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

बिना बिजली, बिना शौचालय वाले उधारी के आगनबाड़ी भवन में उधारी के शिक्षक से चल रहा दाबरीभांटा स्कूल

गरियाबंद। शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावों के बीच देवभोग विकासखंड का अंतिम गांव दाबरीभांटा सरकारी व्यवस्थाओं की हकीकत की पोल खोल रहा है शायद यह ब्लॉक का पहला ऐसा प्राथमिक विद्यालय होगा जहां न अपना भवन है न बिजली, न शौचालय और न ही शिक्षक यहां तक कुर्सी-टेबल जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है फिर भी गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश गांव के आगनबाड़ी केंद्र में किया जा रहा हैं वह भी काफी परेशानियों के बीच क्योंकि आगनबाड़ी केंद्र में एक कमरा और एक बांदा है एक कमरे में प्राथमिक शाला के पहली से लेकर पांचवीं तक के 17 बच्चे अध्यन करते हैं तो दूसरे बादे में आगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे मासूम बच्चे होते है स्तिथि इतनी बदतर है कि इसी एक कमरे में पढ़ाई भी होती है और मध्याह्न भोजन भी कराया जाता है जगह के अभाव में बच्चों को न ठीक से बैठने की सुविधा है और न ही पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है ऐसे में बच्चों शौच के लिए खेत खार तालाब का सहारा लेना मजबूरी होता है इसी तरह शिक्षकों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी-टेबल तक उपलब्ध नहीं हैं जबकि स्कूल रंग रोगन कुर्सी टेबल जैसे अन्य स्कूल मेंटेनेंस के लिए राशि भी जारी होती हैं लेकिन पता नहीं वह राशि जिम्मेदारो द्वारा कहा खर्च किया जाता है इसके अलावा आज जब सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कर रही है, तब दाबरीभांटा का यह विद्यालय उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई मजबूरी में बच्चे और शिक्षक बदहाल परिस्थितियों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं अब सवाल यह है कि जब एक सरकारी स्कूल के पास अपना भवन, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, तो आखिर ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? शिक्षा व्यवस्था के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का यह फासला जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांग रहे है इसके साथ आगनबाड़ी भवन में जगह का आभाव होने के चलते बच्चों के लिए मध्यान भोजन रसोइया के घर पर खाना बनाना पड़ता है और उनके घर से स्कूल भोजन पहुंचता है।

प्रशासन की कार्यवाही, 12 ई-रिक्शा, ऑटो चालकों पर जुर्माना

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने यात्री वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान ई.रिक्शा और ऑटो वाहनों के दस्तावेजों के साथ-साथ यातायात नियमों के पालन की गहन जांच की गई। जांच में कई चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ढोते पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 12 ई.रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। संयुक्त दल ने वाहन चालकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, ओवरलोडिंग से बचने तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की समझाइश भी दी। अभियान में तहसीलदार धमतरी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिले में इस तरह के संयुक्त जांच एवं प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

31 जुलाई तक छात्रवृत्ति पोर्टल खुला

कवर्धा। कबीरधाम जिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा तीसरी से बारहवीं तक के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करने के लिए सत्र 2025-26 का छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया है। छूटे हुए विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सत्र 2025-26 से छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया राशन कार्ड आधारित ई-केवाईसी एवं आधार से लिंक बैंक खाते के माध्यम से की जा रही है। जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अभी भी पंजीयन शेष है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विकासखंड के छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से संकुलों के सहयोग से सभी शालाओं की नियमित समीक्षा एवं परीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यार्थियों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने तथा आधार से लिंक बैंक खाते खुलवाने के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करें। निर्देशों में कहा गया है कि 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पूर्व सभी पात्र विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन एवं सत्यापन पूर्ण कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

नव विवाहिता ने लगाई फांसी, पति व सास-ससूर गिरफ्तार

दल्लीराजहरा। वार्ड क्र. 02 गुलमोहर कॉलोनी गुरूर में किराये के मकान मे निवासरत् मीनाक्षी भतरिया उम्र 28 वर्ष अपने मकान के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उसके पति प्रवीण कुमार भतरिया जो रजिस्ट्रार ऑफिस तहसील कार्यालय गुरूर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बतौर आपरेटर का काम करता था, घटना की रिपोर्ट पर थाना गुरूर मे मर्ग क्रमांक 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम किया गया था। मृतिका के परिजनों एवं जांच के दौरान पता चला कि मृतिका नव विवाहिता थी तब मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गुरूर की उपस्थिति में शव का विधिवत् पंचनामा कार्यवाही किया गया। सायबर सेल बालोद की मदद से मृतिका व उसके पति का मोबाईल नंबरों का कॉल डिटेल प्राप्त किया गया तथा मृतिका के मायके पक्ष मृतिका की मां पुष्पा बाई खरे, पिता अजय खरे, बहन माधवी खरे, भाई अनिल कुमार व अन्य सामाजिक व्यक्तियों का कथन लिया गया तो पता चला कि मृतिका मीनाक्षी भतरिया को विवाह उपरांत उसके पति प्रवीण कुमार भतरिया व ससुर पग्गू लाल भतरिया, सास गीता भतरिया व डेढ़सास करूणा भतरिया द्वारा मृतिका मीनाक्षी भतरिया को कम दहेज लायी हो, यह कहकर अक्सर ताने दिया करते थे तथा यह भी कहा गया कि उसे नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। तुम हम लोगों को पसंद नही हो, रंग रूप व दहेज की बातों को लेकर बार-बार प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर मीनाक्षी भतरिया 24 फरवरी को अपने किराये के मकान गुरूर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संपूर्ण मर्ग जांच पर मामला धारा 80(1), 80(2), 3(5) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध कायमी के तत्काल बाद एसडीओपी गुरूर माया शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपीगणों को उसके निवास ग्राम पथर्रा जिला दुर्ग भेजकर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया, जिनसे घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ करने पर अपराध का घटित करना पाया गया। प्रकरण में मृतिका के पति प्रवीण कुमार भतरिया व उसका ससुर पग्गू लाल भतरिया, सास गीता भतरिया व डेढ़सास करूणा भतरिया के विरूद्ध दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के संबंध में पर्याप्त अपराध धारा का सबूत पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर रिमाण्ड में सीजेएम न्यायालय बालोद पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण की जांच व विवेचना कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक माया शर्मा एसडीओपी गुरूर, निरीक्षक मुकेश सिंह, सहा.उपनिरीक्षक कुलेश्वर यादव, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक वीणा मरावी, आरक्षक पिताम्बर निषाद, विवेक सिन्हा एवं कोमल साहू थाना गुरूर का सराहनीय भूमिका रहा।

भू-जल संरक्षण के लिए जिले में 2.36 लाख कंटूर एवं स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण

दल्लीराजहरा। जल संरक्षण और भू-जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)', अन्य विभागों तथा जनभागीदारी के समन्वय से जिले में 2.36 लाख कंटूर एवं स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। मानसून की पहली बारिश के उपरांत ही इन संरचनाओं में पानी भर जाने से जल का संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण सुनिश्चित हो गया है। कलेक्टर दिव्या मिश्रा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चन्द्रवंशी के नेतृत्व में जिले में 'जल संचय जन भागीदारी अभियान' के अंतर्गत जून 2025 से मई 2026 तक कुल 2,84,917 विभिन्न जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें मुख्य रूप से कंटूर ट्रेंच, तालाब गहरीकरण, तटबंध निर्माण, चेक डैम, सामुदायिक व निजी डबरी, रिचार्ज पिट, सोकपिट, लूज बोल्डर चेकडैम, रूफवॉटर हार्वेस्टिंग एवं गैबियन संरचनाएं शामिल हैं। इन पुख्ता प्रबंधों से वर्षा का बहुमूल्य जल बहकर नष्ट होने के विपरीत अब भूमि में समाहित हो रहा है, जिससे जिले के जल स्रोतों में लंबे समय तक पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। जल की उपलब्धता बढ़ने से क्षेत्र में पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन एवं अन्य ग्रामीण गतिविधियों सहित स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता तथा ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बूस्ट, छग सरकार लाएगी एप

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त श्री एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में परिवहन विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, ऊर्जा विभाग, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ मौजूद रहे। अभी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म/एप बनाएगी। भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप ला रही है। चिप्स के जरिए ऊर्जा विभाग पहले ही पायलट एप पर काम कर रहा है। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने पर वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रोत्साहनों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी जिलों के आरटीओ/डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी के निर्माताओं ने राज्य में लगे और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी और आगे विस्तार की योजना बताया। सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि ईवी चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क बनाना और लोगों को समय पर जानकारी देना जरूरी है। इससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य राज्यभर में आसान और सुलभ चार्जिंग सुविधा देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

डुंडा में लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग कारगर रोक

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन अभियंता गजाराम कंवर, सहायक अभियंता सुशील अहीर, उप अभियंता नवीन वर्मा कार्य सहायक जितेन्द्र कौशिक सहित जोन 10 नगर निवेश विभाग के सम्बंधित कर्मचारियो की स्थल पर उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अतर्गत बाबू जगजीवन राम वार्ड क्रमांक 53 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा में ममता विहार क्षेत्र के समीप लगभग 5 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर वहा पहुंचकर निर्मित की गई अवैध मुरम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर तत्काल रोक लगायी। वहा जाने का मार्ग बाधित किया , साथ ही स्थल पर अवैध नींव को तोड़ा । अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी एवं नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा रायपुर तहसील कार्यालय में तहसीलदार रायपुर को पत्र लिखकर संबंधित भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी के सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र देने का अनुरोध पत्र में किया गया है। तहसीलदार कार्यालय रायपुर से इस सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी आने पर राज्य शासन के अधिनियम के अनुसार संबंधित अवैध प्लाटिंगकर्ता पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने सबधित पुलिस थाने में नामजद एफआईआर दर्ज नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा करवायी जाएगी।

रायपुर नाका में जुए पर बड़ी कार्रवाई, 12 जुआरी गिरफ्तार; 9.04 लाख नकदी और 10 मोबाइल जब्त

रायपुर। थाना मोहन नगर पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 9.04 लाख नकद, 10 मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां जब्त की हैं।पुलिस के अनुसार 8 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर नाका क्षेत्र में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए-पैसों का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया।कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से ?9,04,000 नकद, 10 मोबाइल फोन तथा जुआ खेलने में प्रयुक्त ताश की गड्डियां बरामद कर जब्त की गईं।इस संबंध में थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 473/2026 दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।गिरफ्तार आरोपियों में मयंक गावड़े (भिलाई), प्रह्लाद शर्मा (चिल्फी), राजीव तिवारी (रायपुर), हेमलाल ढीमर (भिलाई), मनीष रात्रे (बेमेतरा), पंकज कुमार काठले (कबीरधाम), दुर्गेश कुमार बर्मन (कबीरधाम), नागेश्वर साहू (रायपुर), पंकज वर्मा (दुर्ग), हेमनंदन डहरे (कबीरधाम), संजय चोपड़ा (रायपुर) और अमित सिंह (दुर्ग) शामिल हैं।पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे।

रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) ने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक नागरिक बिना कार्यालय आए घर बैठे ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन एवं बुकिंग कर सकेंगे। प्राधिकरण ने प्रथम चरण में लगभग 121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें कमल विहार तथा रावभाटा सहित प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं की संपत्तियां शामिल हैं। कमल विहार में आवासीय फ्लैट, आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं, जबकि रावभाटा में व्यावसायिक संपत्तियां बुकिंग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुरूप आवास उपलब्ध कराया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ अब हितग्राही घर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से मेंटेनेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। इससे नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और सेवाएं अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध तथा पारदर्शी बनेंगी। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदे साहू ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक, पारदर्शी एवं जनहितैषी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से समय की बचत होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी तथा संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी।

ग्राम रीवा में 4 करोड़ रुपये के स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा

सुशासन,विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है-साय

- आरंग विधानसभा के विकास को मिली नई गति, 128 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय समोदा में लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की कार्यशैली और जनविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10 लाख से

अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 28 किस्तों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित प्रशासन स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज एवं कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु के माध्यम से 520 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। पात्र उपभोक्ता मोर बिजली मोबाइल एप अथवा वेबसाइट के माध्यम से सितंबर तक पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंग विधानसभा क्षेत्र को अब तक 858 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है।

जोगी कांग्रेस 2.0 की शुरुआत,अमित जोगी ने नए विजन और युवा नेतृत्व के साथ किया बड़ा ऐलान

- युवा विंग का बदला नाम, नशा, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान की घोषणा; कांग्रेस में विलय पर भी रखा पक्ष

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) ने नए स्वरूप और नई रणनीति के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष -अमित जोगी- ने रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जोगी कांग्रेस 2.0- लॉन्च करते हुए पार्टी का नया विजन और भविष्य की रणनीति प्रस्तुत की। अमित जोगी ने कहा कि वर्तमान समय की राजनीति पारंपरिक सोच से आगे बढ़ चुकी है और अब नई तकनीक, नई सोच तथा युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब वंशवाद, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के जमीनी मुद्दों पर काम करेगी। इस अवसर पर पार्टी के युवा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए -अजीत जोगी युवा कांग्रेस- का नाम बदलकर -जनता युवा कांग्रेस- कर दिया गया। पार्टी संस्थापक -अजीत जोगी- के नाम को युवा विंग से हटाने का निर्णय लिया गया। जनता युवा कांग्रेस की कमान -ईश्वर उपाध्याय- को सौंपी गई है, जो अब युवा संगठन का नेतृत्व करेंगे। अमित जोगी ने घोषणा की कि

पार्टी प्रदेशभर में -नशा, बेरोजगारी और अन्याय- के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि जनता युवा कांग्रेस -- बेटी बचाओ-- के साथ-साथ -बेटा बचाओ-- अभियान भी शुरू करेगी। उनका कहना था कि प्रदेश के युवाओं को नशे, बेरोजगारी और अवसाद से बचाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि शराब सेवन और मादक पदार्थों के बढ़ते उपयोग को लेकर राज्य गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस में विलय चाहती थी और इसके लिए लगभग एक वर्ष पहले कांग्रेस हाईकमान को पत्र भी भेजा गया था। हालांकि, अब तक कोई निर्णय नहीं होने के कारण पार्टी ने अपने संगठन को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वर्तमान समय में सहयोग की आवश्यकता है और उनकी पार्टी भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस का सहारा बनना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जोगी कांग्रेस पर भाजपा की -बी टीम- होने का जो आरोप लगता रहा, उससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा और जनता के बीच नकारात्मक संदेश गया।

किसान सम्मान निधि से खेती को मिला आर्थिक संबल.....

- हर चार माह में 2 हजार रुपये की किस्त से मिल रही राहत
- एमसीबी के किसान संतोष कुमार ने जताया आभार

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। हर चार माह में मिलने वाली 2 हजार रुपये की किस्त से किसान खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम भल्लौर निवासी किसान संतोष कुमार कुशवाहा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। उनके अनुसार, योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6 हजार रुपये की राशि खाद, बीज, कृषि सामग्री तथा खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है। पहले खेती के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मिलने वाली सहायता से कृषि कार्य बेहतर ढंग से पूरे हो रहे हैं। संतोष कुमार ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग है। खेती के समय मिलने वाली यह राशि जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है और कृषि कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित इस योजना से देशभर के किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। संतोष कुमार ने प्रदेश सरकार की कृषि उन्नति योजना की सराहना करते हुए कहा कि धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। इससे किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है और खेती के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है। संतोष कुमार कुशवाहा ने कहा - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि खेती के समय बहुत काम आती है। इससे खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं से हमें काफी लाभ मिल रहा है और अब हमें महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत को सही सम्मान मिल रहा है।

पूर्व मंत्री मो. अकबर की पहल का असर

मई तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी,जून माह की प्रक्रिया भी शुरु..

- राज्यपाल को पत्र लिखकर किया था पेंशन दिलाने का आग्रह

रायपुर। संवाददाता

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित भुगतान को लेकर राज्यपाल को लिखे गए पत्र के बाद अब हितग्राहियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने मई 2026 तक की लंबित पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है, जबकि जून माह की पेंशन जारी करने की

प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने 5 जून को राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाखों हितग्राहियों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि लगातार बढ़ती महंगाई और भीषण गर्मी के बीच गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों के लिए पेंशन ही जीवनयापन का प्रमुख सहारा है, ऐसे में भुगतान में देरी से वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पत्र में अकबर ने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया था, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर पेंशन मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि किसी कारणवश केंद्र से राशि मिलने में देरी हो रही हो।

महिला से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार किए

रायपुर। जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार घटना 27 जून की देर शाम की है। पीड़िता अपने पति के साथ बाजार से गांव लौट रही थी। रास्ते में उसका पति शराब के नशे में सो गया। इसी दौरान चार युवकों ने कथित रूप से महिला को जबरन पास के एक खेत में ले जाकर उसका मुंह दबाया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

मंत्री ने निर्माण कार्यों की गहन मॉनिटरिंग और निरीक्षण के दिए निर्देश

- लोक निर्माण विभाग राज्य का 'ग्रोथ इंजन', विभाग पर अधोसंरचना विकसित करने की अहम जिम्मेदारी
- सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश, अनुबंध अनुसार प्रगति सुनिश्चित कर समय-सीमा में काम पूरा कराने कहा

रायपुर/ संवाददाता

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय 'निर्माण भवन' में प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए

अधिकारियों को प्रत्येक कार्यों की प्रगति पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद रख कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखनी चाहिए। उन्होंने प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यों के लिए समयानुकूल नई कार्यप्रणाली और कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तत्परता से पूर्ण कर आगामी सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि बरसात के तत्काल बाद पूरी गति से काम शुरू हो सके। उन्होंने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूर्ण कर समय पर काम प्रारंभ कराने को कहा। श्री साव ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य का 'ग्रोथ इंजन' है। राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के साथ ही सभी तरह की अधोसंरचना विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विभाग को भी अहम भूमिका निभाना है। उन्होंने इसके लिए पूरी सक्रियता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को काम का पुराना ढर्रा बदलने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के समय पर बिल तैयार करने और उनका हर महीने भुगतान करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि फील्ड पर विभाग के काम और उनके परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने सड़कों और पुल-पुलियों सहित स्कूलों, कॉलेजों, ऑडिटोरियम, कार्यालयों, आवासगृहों एवं अन्य भवनों के निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के साथ अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कर समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा। उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को भू-अर्जन के कार्यों में तेजी लाने इससे संबंधित कानूनों व नियमों की व्यापक एवं समग्र जानकारी के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों तथा उप अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने पहुंचविहीन गांवों तक साल भर कनेक्टीविटी बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों के प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राथमिकता से तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

संपादकीय

इंस्टाग्राम पर बढ़ रहा बाल यौन शोषण, साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है?

इंटरनेट की दुनिया ने इंसानी समाज के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई हैं और इसकी उपयोगिता को देखते हुए ही इसका दायरा फैल रहा है।इंटरनेट की दुनिया में अनेक स्तर पर लोगों के ठगी का शिकार होने से लेकर 'डिजिटल अरेस्ट' और अन्य गंभीर अपराधों के फैलते जाल ने वैश्विक स्तर पर एक जटिल चुनौती पेश की है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो तकनीक लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने, उनकी समझ का विस्तार करने के काम में आनी चाहिए थी, वह अब कुंठित और आपराधिक मानसिकता के लोगों के लिए एक कारगर औजार बन रही है।ताजा विवाद सोशल मीडिया के एक लोकप्रिय मंच 'इंस्टाग्राम' से जुड़ा है, जिस पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन दिखाने का आरोप है, जिसके जरिए बच्चे-बच्चियों के यौन शोषण की सामग्री का प्रसार हो रहा है। यही नहीं, उपयोगकर्ताओं को बच्चों के यौन शोषण के वीडियो मामूली खर्च पर खरीदने के लिए ऑनलाइन संपर्क भी दिए जा रहे हैं।सवाल है कि अगर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां व्यापक पहुंच रखने वाले एक लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच पर चलाई जा रही हैं, तो इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्हें बिना बाधा के यह सब करने की छूट और सुविधा कौन मुहैया करा रहा है। क्या 'इंस्टाग्राम' और उसकी संचालक कंपनी 'मेटा' की इसके लिए सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह अपने मंच पर आपराधिक हरकतों को फलने-फूलने की जगह दे रही है?यह बेवजह नहीं है कि सरकार ने बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों के मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। हाल ही में सरकार ने मेटा के ही स्वामित्व वाले वाट्सऐप को उसकी नई उपयोगकर्ता सुविधा के मामले में नोटिस भेजा था, जिसमें नाम छिपाकर बात करने की छूट दी गई है। कहने को सोशल मीडिया के मंचों के अपने नियम-कायदे या दिशानिर्देश होते हैं, जिनके तहत वे आपत्तिजनक सामग्री को हटा देते हैं।मगर ऐसा लगता है कि 'आपत्तिजनक सामग्री' की परिभाषा ये कंपनियां अपनी सुविधा और एजंडे के मुताबिक तय करती हैं। वरना सामाजिक और कानूनी तौर पर भी अपराध के दायरे में मानी जाने वाली अश्लील और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ सख्ती और उन पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर वे उदासीन क्यों रहती हैं? ऐसे में यह क्यों नहीं माना जाए कि वे आपत्तिजनक सामग्री को प्रसारित करने के जरिए सिर्फ अपनी कमाई सुनिश्चित करती हैं और प्रकारांतर से वे भी ऐसी हरकतों की भागीदार होती हैं?यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम पर विज्ञापन तभी जारी होते हैं, जब उसके मातहत काम करने वाले तंत्र की बेहद आधुनिक तकनीक उसे सही बताती है। ऐसे में जिस डिजिटल संसार में तेजी से साइबर अपराध का दायरा फैलता जा रहा है, उसमें आपराधिक हरकतों पर रोक लगाने के प्रति उदासीनता बरतने को कैसे देखा जाएगा? कोई भी तकनीक अपने आप में एक निरपेक्ष साधन है।

सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में सब्सिडी को लेकर लोक लुभावन वादे तो जरूर किए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि सरकार पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी के पेंडिंग मामलों का निपटारा कब तक करेगी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत 4 हजार से अधिक लोगों को सब्सिडी का इंतजार है और इन लोगों को मिलने वाली राशि करीब 7.5 करोड़ रुपए है। पुरानी सब्सिडी के लंबित मामलों में एक केस मेरा भी है। मैंने (कपिल तिवारी) मई 2023 में अथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर लाजपत नगर स्थित एक डीलर से खरीदा था। उस समय दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के तहत मुझे 18,300 रुपए की सब्सिडी मिलनी थी जिसका भरोसा मुझे वाहन खरीदते वक्त डीलर की ओर से दिया गया था। सरकार की घोषित योजना के अनुसार, निर्धारित समय (3-4 महीने) में यह राशि मेरे बैंक अकाउंट में आनी थी, लेकिन आज तीन साल से अधिक का समय बीत चुका है और मुझे मेरी सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी पर कैसे भरोसा करें लोग? 3 साल से अटकी है पुरानी सब्सिडी

(कपिल तिवारी)

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अधिक से अधिक निर्भर कराया जाए।

दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है। नई पॉलिसी के जरिए सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि मार्च 2030 तक दिल्ली को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर किया जाए। इसके लिए सरकार ने नई पॉलिसी में कई ऐसे नियम और कई ऐसे लाभ लोगों के लिए रखे हैं जो दिल्लीवासियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसमें सबसे खास जो नियम सरकार की ओर से रखा गया है वह है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि यानी कि सब्सिडी, जी हां नई पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से ईवी टू व्हीलर पर 30 हजार रुपए तक की, थ्री व्हीलर पर 50,000 रुपए तक की और चार पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा लाइट कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों (अधिकतम वजन 3,500 किलोग्राम तक) की खरीद पर भी 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी।

नई पॉलिसी से पहले पुराने वादे भूली सरकार?

सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में सब्सिडी को लेकर लोक लुभावन वादे तो जरूर किए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि सरकार पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी के पेंडिंग मामलों का निपटारा कब तक करेगी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत 4 हजार से अधिक लोगों को सब्सिडी का इंतजार है और इन लोगों को मिलने वाली राशि करीब 7.5 करोड़ रुपए है। पुरानी सब्सिडी के लंबित मामलों में एक केस मेरा भी है। मैंने (कपिल तिवारी) मई 2023 में अथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर लाजपत नगर स्थित एक डीलर से खरीदा था। उस समय दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के तहत मुझे 18,300 रुपए की सब्सिडी मिलनी थी जिसका भरोसा मुझे वाहन खरीदते वक्त डीलर की ओर से दिया गया था। सरकार की घोषित योजना के अनुसार, निर्धारित समय (3-4 महीने) में यह राशि मेरे बैंक अकाउंट में आनी थी, लेकिन आज तीन साल से अधिक का समय बीत चुका है और मुझे मेरी सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार की नई ईवी पॉलिसी पर होगा भरोसा?

यहां बात सिर्फ 18,300 रुपए की सब्सिडी की नहीं है बल्कि सरकार के उस भरोसे पर सवाल है जिसके आधार पर लोगों ने पेट्रोल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का फैसला किया है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए लोग ईवी पर शिफ्ट करें और सरकार की ओर से मिलने वाले आर्थिक प्रोत्साहन का लाभ लें। अगर उस प्रोत्साहन राशि को पाने के लिए सालों का इंतजार करना पड़े तो फिर ऐसे भरोसे का क्या फायदा? ऐसे में सरकार की नई ईवी पॉलिसी पर लोगों का भरोसा कैसे कायम होगा?

डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट फिर भी नहीं आई सब्सिडी

बीते तीन सालों में मैंने सब्सिडी के लिए उस डीलर से जिससे ईवी स्कूटर खरीदा था और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग दोनों जगह कई बार संपर्क किया। 3-4 बार मैंने विभाग को ईमेल के जरिए अपनी जानकारी भेजकर अपनी समस्या से अवगत कराया है, लेकिन मुझे विभागीय तौर पर कोई मदद नहीं मिली है और ना ही सब्सिडी की राशि मेरे अकाउंट में आई है। यहां तक कि 3 साल में अनगिनत बार मैं दिल्ली सरकार के सिविल लाइन में स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी जा चुका हूं और हर बार मुझे सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि सरकार की ओर से पैसा भेजा जा रहा है और बहुत जल्द आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाएगी। विभाग की ओर से बीते तीन साल में मैंने यहां तक भी सुना है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट है और पैसा जल्द ही अकाउंट में आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन 3 साल से कंप्लीट है तो फिर पैसा ट्रांसफर होने में इतनी देरी कैसे?

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताजा अपडेट क्या मिला?

मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में आखिरी विजिट पिछले महीने (जून में) ही किया था। उस वक्त मुझे विभाग के अधिकारियों की ओर से यही कहा गया कि सरकार ने पेंडिंग सब्सिडी के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सरकार की ओर से फंड भी रिलीज किया जा रहा है। आपकी सब्सिडी का काम डॉक्यूमेंट की वजह से बिल्कुल नहीं रुका है बल्कि सरकार की ओर से फंड नहीं आने की वजह से अभी तक यह केस पेंडिंग था, आप अगले 4-6 महीने का इंतजार और कीजिए आपको आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। अधिकारियों की ओर से ये कहा गया था कि डिपार्टमेंट की ओर से पेंडिंग सब्सिडी के मामले सेटल्ड किए जा रहे हैं।

4 हजार से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी का इंतजार

दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल की ओर से मार्च 2026 में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, पुरानी ईवी पॉलिसी के तहत कुल 22,733 सब्सिडी क्लेम पेंडिंग थे। डी-डुप्लीकेशन और आधार वैलिडेशन के बाद कुल 16,892 अलग-अलग केस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के पास भेजे गए। इनमें से 12,877 लाभार्थियों को मार्च 2026 तक पैसा भेज दिया गया है। इनकी राशि करीब 24 करोड़ रुपए के करीब थी। वहीं 4015 लाभार्थियों को 7.3 करोड़ की राशि भेजा जाना बाकी है। यह लोग आधार वेरिफिकेशन से गुजर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने पेंडिंग सब्सिडी का निपटारा भी तब शुरू किया था जब पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को पेंडिंग ईवी सब्सिडी तुरंत देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रोसेस में देरी की वजह से पेमेंट रोकना सही नहीं है और दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2020 में पेमेंट की कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है।

नई पॉलिसी में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए

सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में चाहे कितनी भी आकर्षक घोषणाएं क्यों न कर दी हों, लेकिन सबसे पहले उन लोगों का विश्वास लौटाना जरूरी है जिन्होंने पुरानी पॉलिसी पर भरोसा किया था। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन लाभार्थियों की सब्सिडी लंबित है उनका भुगतान कब तक होगा। यदि किसी प्रशासनिक या तकनीकी कारण से देरी हुई है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा भी घोषित की जानी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि नई पॉलिसी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यदि किसी खरीदार को सब्सिडी मिलनी है तो वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सके। भुगतान में देरी होने पर उसका कारण और संभावित समय भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और सरकार की नीतियों की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।

आखिर में सरकार से मेरी अपेक्षा केवल इतनी है कि वह नई शुरुआत करने से पहले पुरानी जिम्मेदारियों को पूरा करे। यदि सरकार वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे सबसे पहले उन नागरिकों का विश्वास लौटाना होगा जिन्होंने उसकी नीति पर भरोसा किया था। नई ईवी पॉलिसी का स्वागत तभी सार्थक होगा जब पुरानी ईवी पॉलिसी के लाभार्थियों के साथ किया गया वादा भी पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा।

लंदन से दिखी भारत की तस्वीर- विकास के दावों के बीच क्यों बढ़ रही हैं लोगों की उम्मीदें?

(तवलीन सिंह)

हम सब जानते हैं कि हमने ऐसा देश बनाया है, जिसमें आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में पर्याप्त निवेश नहीं किया। हम यह भी जानते हैं कि सबसे बड़ा दोष हमारे शासकों का है, जिन्होंने अपने परिवारों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन इस कोशिश में वे उन लोगों को भूल गए, जिनके वे स्वयं को सेवक कहते नहीं थकते।

करीब दस सालों बाद लंदन आई हूं। यह लेख वहीं से आ रहा है आपके पास। यहां एयर इंडिया की उड़ान से आई थी और हैरान हुई देखकर कि कितने भारतीय विदेश में घूमने लग गए हैं। मेरी उड़ान में तकरीबन सारे यात्री अपने ही देशवासी थे और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें एक बड़ा समूह गुजराती महिलाओं का था, जो पारंपरिक घाघरा-दुपट्टा पहने हुए थीं और जिन्हें अंग्रेजी का एक शब्द नहीं मालूम था।

बहुत अच्छा लगा इन्हें देखकर, इसलिए कि जब ऐसे लोग विदेश का सफर करने लगेंगे, तो उनकी अपने राजनेताओं से अपेक्षाएं भी अधिक होने लगेंगी। वे चीजें मांगने लगेंगे, जो अभी तक देश के मतदाताओं को किसी भी सरकार से नहीं मिली हैं।

माना कि नरेंद्र मोदी के राज में विकास के तौर पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आम लोगों के जीवन में इसका असर कम रहा है, इसलिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बल्कि स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसर और भी बदतर हो गए हैं।

संयोग नहीं है कि काकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन पिछले दो हफ्तों से जंतर-मंतर पर चल रहा है, उसकी मांगें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इस प्रदर्शन के बारे में आपको खबर कम ही मिली होगी, क्योंकि मीडिया ने जैसे इसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। इससे ही जान जाइए कि सरकार को इस प्रदर्शन से तकलीफ हो रही है। हमारे तमाम बड़े राजनेता इस प्रदर्शन पर कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि बोलें तो बोलें क्या और करें तो करें क्या। अब अगर शिक्षा मंत्री की नौकरी जाती है, तो ऐसा लगेगा कि नौजवानों के दबाव में ऐसा हुआ है। मगर यह अच्छा नहीं है कि देश के युवाओं की बात सुनी नहीं जा रही है।

लंदन उन विदेशी महानगरों में है, जहां हर जगह आपको भारतीय नौजवान काम करते हुए दिखेंगे। यहां तक कि हवाईअड्डे पर पासपोर्ट जांच करने वाले भी अब भारतीय हैं। कभी वह जमाना था, जब अपने देसी भाई-बहन हवाईअड्डे पर सिर्फ सफाई कर्मचारी थे, लेकिन उनके बच्चे अब ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, जिनके लिए शिक्षित होना और कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है।

मैंने जब एक-दो लोगों से पूछा कि वे देश वापस क्यों नहीं जाना चाहते, तो उनका जवाब यही था कि जरूर जाते, अगर उनकी कमाई इतनी होती कि इज्जत से जी सकें। हम जानते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है अपने देश में।

आर्थिक शरणार्थी हैं ये लोग। अफसोस की बात यह है कि हमारे सबसे शिक्षित लोग भी आर्थिक शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं। एआई के क्षेत्र में इतने भारतीय मूल के लोग अमेरिका में मिलते हैं कि भारतीयों के खिलाफ एक मुहिम-सी चलने लगी है कैलिफोर्निया में। कोई राज की बात नहीं है कि अमेरिका की कई सबसे बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग चलाते हैं।

रही बात लंदन की, तो यहां कई सबसे धनवान भारतीय बस गए हैं। वे भारत में निवेश करते हैं, लेकिन वहां रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो सुविधाएं उन्हें लंदन में मिलती हैं, वे मुंबई और दिल्ली में नहीं मिलतीं।

स्वच्छ सड़कें, सुंदर रिहाइशी इलाके और बड़े-बड़े पार्क, जिनमें जहरीली हवा की चिंता के बिना टहला जा सके, और साफ पीने का पानी। ऊपर से मनोरंजन के कई साधन। फिलहाल लंदन में विंबलडन चल रहा है, जिसे देखने हर साल कई देशों से लोग आते हैं।

हमारे देश में आईपीएल के अलावा कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इसे शुरू किया था, वह भी तब से लंदन में रहता है, जब से उसे अपने देश के आला राजनेताओं ने देश से बाहर कर दिया। ललित मोदी ने हाल में कई पत्रकारों से बातचीत में माना है कि उनकी जान को दाऊद इब्राहिम से खतरा था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनेता और क्रिकेट प्रशासन के कई आला अधिकारी उनसे नाराज थे।

मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। हम सब जानते हैं कि हमने ऐसा देश बनाया है, जिसमें आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में पर्याप्त निवेश नहीं किया। हम यह भी जानते हैं कि सबसे बड़ा दोष हमारे शासकों का है, जिन्होंने अपने परिवारों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन इस कोशिश में वे उन लोगों को भूल गए, जिनके वे स्वयं को सेवक कहते नहीं थकते।

हमारे स्कूलों और अस्पतालों का सुधार क्यों करें, जब वे जानते हैं कि उनके बच्चे तो निजी सुविधाओं का ही इस्तेमाल करने वाले हैं? बरसात और गर्मी के मौसम में शहरों और महानगरों की बदहाल सुविधाओं को क्यों दुरुस्त करें, जब वे जानते हैं कि वे खुद लंदन और न्यूयॉर्क में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं?

दोष सबसे अधिक हमारे राजनेताओं और शासकों का है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ दोष हमारा भी है कि हम इन सारी चीजों को देखते हुए भी विरोध की आवाज नहीं उठाते। हम मीडिया वालों को भी शर्मिंदगी से सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब नौजवानों का प्रदर्शन पिछले दो हफ्तों से दिल्ली में चल रहा है, तब हम जानबूझकर उसके बारे में न लिख रहे हैं, न टीवी पर चर्चा कर रहे हैं।

काकरोच जनता पार्टी की खबरें लेनी हों, तो सोशल मीडिया पर जाना पड़ता है, जहां वे दुखी माता-पिता दिखाई देते हैं, जिनके बच्चों ने नीट के प्रश्नपत्र बार-बार लीक होने से तंग आकर आत्महत्या कर ली है।

हर साल करोड़ों पौधे लगाए जा रहें, फिर भी घटती हरियाली! आखिर कहां गायब हो जाते हैं वृक्ष?

हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, हर साल आंकड़े दिखाए जाते हैं। मगर हर बार जमीन पर हरियाली उतनी ही कम होती चली जाती है। यह उस तंत्र की स्वाभाविक परिणति है, जहां जवाबदेही की जड़ें उतनी ही कमजोर हैं, जितनी सड़क किनारे ग` में ठूंस दिए गए उस पौधे की, जिसे न पानी मिलेगा, न देखभाल होगी और न जीवित रहने का कोई वास्तविक अवसर मिलेगा। दिल्ली का उदाहरण इस स्थिति का सबसे सटीक आईना है। पिछले चार वर्षों में राजधानी में दो करोड़ पांच लाख पौधे लगाए गए, लेकिन उनमें से केवल 60 फीसदी ही जीवित रह सके। यह उस शहर का हाल है, जहां सरकारी निगाह सबसे अधिक रहती है।

(देवेंद्रराज सुथार)

पिछले चार वर्षों में राजधानी में दो करोड़ पांच लाख पौधे लगाए गए, लेकिन उनमें से केवल 60 फीसदी ही जीवित रह सके। यह उस शहर का हाल है, जहां सरकारी निगाह सबसे अधिक रहती है। आज जब अल-नीनो की मार, रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी और गहराता सूखा हर वर्ष के साथ विकराल होता जा रहा है, तब पौधारोपण को एक औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि एक कानूनी दायित्व की तरह देखने की जरूरत है।

मानसून की पहली बारिश जैसे ही धरती को भिगोती है, सरकारी तंत्र सुपरिचित रस्म-अदायगी में जुट जाता है। वन विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं लाखों पौधे लगाने के लक्ष्य तय करती हैं, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करती हैं और अगले मानसून तक इस पूरे उपक्रम को विस्मृत कर देती हैं। हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, हर साल आंकड़े दिखाए जाते हैं। मगर हर बार जमीन पर हरियाली उतनी ही कम होती चली जाती है। यह उस तंत्र की स्वाभाविक परिणति है, जहां जवाबदेही की जड़ें उतनी ही कमजोर हैं, जितनी सड़क किनारे गड्ढे में ठूंस दिए गए उस पौधे की, जिसे न पानी मिलेगा, न देखभाल होगी और न जीवित रहने का कोई वास्तविक अवसर मिलेगा। दिल्ली का उदाहरण इस स्थिति का सबसे सटीक आईना है। पिछले चार वर्षों में राजधानी में दो करोड़ पांच लाख पौधे लगाए गए, लेकिन उनमें से केवल 60 फीसदी ही जीवित रह सके। यह उस शहर का हाल है, जहां सरकारी निगाह सबसे अधिक रहती है। दूरदराज के जिलों और गांवों में तो यह दर और भी दयनीय है।

जब वन आवरण बढ़ने की घोषणाएं की जाती हैं, तो उनके दावों की पड़ताल जरूरी हो जाती है। दिसंबर 2024 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023 में कहा गया कि 2021 से देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और यह 2023 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 फीसदी हो गया है। इसी रिपोर्ट पर पर्यावरणविदों ने तीखी आपत्ति जताई। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि सरकार ने बांस के बागान, नारियल के पेड़ों और बागों को वन आवरण के हिस्से के रूप में गिना और बड़ा-चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़ों के साथ एक दोषपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। रबर, यूकेलिप्टस और बबूल के बागान जैव विविधता के लिहाज से उन सघन प्राकृतिक वनों की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते, जो सदियों में विकसित हुए थे और जिनका एक-एक पेड़ सैकड़ों जीव-जंतुओं का आश्रय था।

वनों की निगरानी रखने वाले मंच 'ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच' के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2001 से 2024 के बीच भारत ने 23.1 लाख हेक्टेयर हरित आवरण खो दिया, जो वर्ष 2000 की तुलना में 7.1 फीसदी की गिरावट है। इससे 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ और वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई के मामले में भारत वर्ष 2015 से 2020 के बीच दूसरे स्थान पर रहा, जहां प्रतिवर्ष 6.68 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ। यह तथ्य अकेले ही पूरी बहस की दिशा तय कर देता है। विकास की हर परियोजना, हर राजमार्ग, हर बांध, हर खदान पहले पेड़ों का बलिदान मांगती है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि, मध्य भारत में खनन और पश्चिमी घाटों पर सड़क निर्माण व पर्यटन का दबाव मिलकर उस वन संपदा को नष्ट कर रहे हैं, जिसे बनाने में प्रकृति को हजारों वर्ष लगे। दुनिया में प्रति व्यक्ति औसतन 400 पेड़ हैं, जबकि भारत में यह संख्या

इससे कहीं कम है। जिस देश में चिपको आंदोलन चला, वहीं बिना सोचे-समझे पेड़ काट दिए जाते हैं।

ऐसे में जब कनाडा के क्यूबेक प्रांत के एक छोटे कस्बे से खबर आती है कि उसने आधिकारिक रूप से पेड़ों को अपने अधिकारों वाले जीवित प्राणी के रूप में मान्यता दी है, तो उस पर ध्यान जाता है। ओंटारियो में म्युनिसिपल एक्ट-2001 के तहत नगरपालिकाओं को पेड़ों की सुरक्षा के लिए विस्तृत उपनियम बनाने का अधिकार मिला हुआ है और इसे जमीन पर लागू भी किया जाता है। टोरंटो में पेड़ काटने पर जुर्माना 500 से एक लाख डॉलर प्रति पेड़ तक हो सकता है और अतिरिक्त एक लाख डॉलर गंभीर उल्लंघन के लिए निर्धारित है। इसी का परिणाम है कि टोरंटो प्रतिवर्ष लगभग एक लाख 20 हजार पेड़ लगाता है और शहर में अनुमानित एक करोड़ 15 लाख पेड़ों का प्रबंधन करता है, जिनसे प्रतिवर्ष पांच करोड़ 50 लाख डॉलर से अधिक का पर्यावरणीय लाभ मिलता है। यह पर्यावरण की नहीं, अर्थशास्त्र की भी भाषा है। भारत में यह सोच अभी तक न नीतियों में उतरी है, न प्रशासनिक ढांचे में।

इथियोपिया का उदाहरण प्रेरक और उससे भी ज्यादा शिक्षाप्रद है। बीसवीं सदी के आरंभ में इथियोपिया की 35 फीसदी भूमि वन से आच्छादित थी, जो वर्ष 2000 तक घटकर केवल चार फीसदी रह गई थी। इस गिरावट को रोकने के लिए इथियोपिया ने जो रास्ता अपनाया, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। जुलाई 2019 में उसने देशभर में एक हजार निर्धारित स्थलों पर महज 12 घंटों में साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए और एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया। इथियोपिया के 'ग्रीन लेगेसी' कार्यक्रम में लगाए गए 70 फीसदी से अधिक पेड़ देशज प्रजातियों के थे, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक रोजगार सृजित किए, जिनमें 60 फीसदी महिलाएं और युवा थे। वर्ष 2019 से 2023 तक इथियोपिया का वन आवरण 17.2 फीसदी से बढ़कर 23.6 फीसदी हो गया। यह वृद्धि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, धरती की वास्तविक हरियाली थी।

इथियोपिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि उसने रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि यह है कि उसने पौधारोपण को एक राष्ट्रीय संकल्प में बदला, जहां नेता, किसान, विद्यार्थी और महिलाएं सब एक साथ खड़े हुए। कोस्टा रीका का अनुभव भी उतना ही सीखने लायक है। इसने 1970 के दशक में, जब उसका वन आवरण केवल 17 फीसदी रह गया था, तब से लेकर 2024 तक उसे 54 फीसदी तक पहुंचाया। इसके पीछे कोई बड़ा धन नहीं था, बल्कि एक सरल और दूरदर्शी नीति थी, जिसमें वन भूमि को बनाए रखने वाले किसानों और जमींदारों को सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया।

रवांडा ने भी अपनी अनूठी सामुदायिक भागीदारी के बल पर वन आवरण को वर्ष 2000 में 10 फीसदी से बढ़ाकर 2024 तक 30 फीसदी से अधिक कर लिया। वहां एक अनूठी व्यवस्था है, जिसके तहत नागरिक हर महीने एक शनिवार की सुबह पर्यावरण कार्यों (जिनमें पेड़ लगाना भी शामिल है) के लिए समर्पित करते हैं। कानून और सामुदायिक जिम्मेदारी के इस संयोजन ने रवांडा को अफ्रीका में वन संरक्षण का अग्रदूत बना दिया। भारत के पास इन सभी देशों से सीखने का अवसर है। यहां न साधनों की कमी है, न भूमि की और न मानव संसाधनों की। कमी है तो केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त कानूनी ढांचे और दीर्घकालिक सोच की। आज जब अल-नीनो की मार, रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी और गहराता सूखा हर वर्ष के साथ विकराल होता जा रहा है, तब पौधारोपण को एक औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि एक कानूनी दायित्व की तरह देखने की जरूरत है। जिस देश में पीपल को पवित्र माना जाता है और बरगद को अमर, उस देश में पेड़ को जीवित प्राणी का दर्जा देने के लिए कानून की नहीं, केवल संकल्प की जरूरत है। इरादा तब बनता है, जब यह समझ आए कि जो पेड़ काटा गया, उसके साथ भविष्य की एक सांस भी काटी गई।

नक्सल मामलों में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर बीजापुर में उमड़ा जनसैलाब

12 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलेंगे पीड़ित परिवार, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। नक्सल मामलों में विभिन्न जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को बीजापुर में बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार और ग्रामीण विधायक विक्रम मंडावी के निवास पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद आयोजित कार्यक्रम में तीन हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया और अपने परिजनों की निशर्त रिहाई की मांग की। बैठक के दौरान परिजनों ने बताया कि वर्षों से जेलों के चक्कर, अदालतों में पेशी और वकीलों की फीस के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, जबकि बच्चों की पढ़ाई और आजीविका भी प्रभावित हो रही है। परिजनों का आरोप है कि महुआ बीनने वाले ग्रामीणों, खेती-किसानी करने वाले किसानों तथा स्कूली छात्रों तक को नक्सल मामलों में जेल भेजा गया है। नक्सल मामलों में जेलों में बंद लोगों के परिजनों ने एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात कर जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग उठाएगा। परिजनों ने यह भी मांग की कि जिस प्रकार आत्मसमर्पण करने वाले हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया गया है, उसी प्रकार निर्दोष आदिवासियों के मामलों की भी समीक्षा कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि एक ओर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर के गरीब आदिवासी वर्षों से नक्सलियों के मददगार बताकर जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का बड़ा वर्ग कानून और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं से परिचित नहीं है, जिसके कारण परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि आगामी 12 जुलाई को पीड़ित परिवारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रायपुर जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर न्याय दिलाने की दिशा में पहल करेगी।बैठक और प्रेस वार्ता के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों और पीड़ित परिवारों ने विधायक कार्यालय से रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नक्सल मामलों में बंद लोगों की निशर्त रिहाई, लंबित मामलों की समीक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, भीमा मड़कम, सोनाराम वारसा, वामन कड़ती, सुखराम, सरिता गोटा, कड़ती वेंकट, हेमला लक्ष्मण, सन्नू कुरसम, शैलेश मड़कम, सोढ़ी रामलू, कुंजाम लक्ष्मा, मंगली अवलम, मोती कोरसा, रमेश लेकाम, पार्वती वेको, रवीना सोढ़ी और रवींद्र उरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पीड़ित परिवार मौजूद थे।

पद्मश्री डॉ. बुधरी तांती से दंतेवाड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की सौजन्य मुलाकात

किरंदुल। प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रानी राव एवं उपाध्यक्ष पार्वती के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवम सदस्यों ने पद्मश्री से सम्मानित डॉ. बुधरी तांती से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संघ के सदस्यों ने डॉ. तांती को पद्मश्री सम्मान मिलने पर बधाई दी और उन्हें बड़ी दीदी कहकर सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष रानी राव ने कहा कि डॉ. तांती का सम्मान पूरे बस्तर के लिए गौरव का विषय हैं। डॉ बुधरी तांती ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के समाज सेवा कार्यों की सराहना भी की।

'दीदी के गोठ' में महिलाओं ने साझा की सफलता की कहानी, 'कांकेयर' ब्रांड की वेबसाइट व पैकेजिंग यूनिट का शुभारंभ

कांकेर। कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत आयोजित मासिक रेडियो कार्यक्रम 'दीदी के गोठ' के 12वें विशेष प्रसारण का आयोजन गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विकासखंडों से आई स्व-सहायता समूहों की महिलाओं एवं लखपति दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बिहान से जुड़कर वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद नाग ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर बड़ी संख्या में महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी ने कहा कि स्व-सहायता समूह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ समाज में अपनी अलग पहचान भी स्थापित कर रही हैं।

गच्छनपल्ली में 20 साल बाद झोपड़ी की जगह खड़ा हुआ पक्का स्कूल

बंदूक की जगह अब ककहरे की सुनाई देगी गूंज

सुकमा। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिले से उम्मीद और बदलाव की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कभी माओवादियों की खूंखार पीएलजीए बटालियन-1 का मजबूत गढ़ रहे बुर्कलंका इलाके का गच्छनपल्ली गांव अब लाल आतंक के साये से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। सुरक्षा बलों की रणनीतिक कार्रवाई और लगातार अभियानों के दम पर प्रशासन ने यहां विकास का नया सवेरा लिखा है। पगडंडियों और दुर्गम रास्तों की परवाह न करते हुए खुद कलेक्टर-एसपी बाइक पर सवार होकर अपनी टीम के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे, उनसे संवाद किया और सुरक्षा के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास का पक्का भरोसा दिलाया। प्रशासन के 'नियद नेल्लनार योजना' (आपका अच्छा गांव) अभियान के तहत आज गच्छनपल्ली के नौनिहालों के चेहरों पर एक नई मुस्कान तैर रही है। करीब दो दशक पहले सलवा जुडूम के दौर में नक्सलियों ने जिस स्कूल भवन को बारूद से ढहा दिया था, वहां आज विकास और विश्वास की एक नई और सुसज्जित पक्की इमारत खड़ी हो गई है। पिछले 20 सालों से यहां के बच्चे बुनियादी शिक्षा के लिए कभी अस्थायी झोपड़ियों तो कभी आंगनबाड़ी के कमरों के सहारे अपने भविष्य की इबारत लिख रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आधुनिक शैक्षणिक माहौल मिल गया है। नए स्कूल भवन का शुभारंभ स्थानीय परंपराओं के अनुसार पूजा-पाठ के साथ बेहद भावुक माहौल में किया गया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए बुर्कलंका पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच, पारंपरिक पेरमा पुजारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण व शिक्षक एकत्र हुए। अपनी आंखों के सामने झोपड़ी की जगह पक्के स्कूल को साकार होते देख ग्रामीणों की आंखें खुशी से छलक उठीं। सालों से जिस बस्तर ने सिर्फ बंदूकों की गूंज सुनी थी, वहां अब बच्चों के खिलखिलाने और ककहरा सीखने की आवाजें गूंज रही हैं। कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि शासन की 'नियद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना के तहत हमारा मुख्य संकल्प नक्सल प्रभावित रहे और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था व विकास को बहाल करना है। गच्छनपल्ली में 20 वर्ष बाद नवीन स्कूल भवन का निर्माण, लाल आतंक के प्रभाव को समाप्त कर प्रशासनिक पहुंच स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। जिला प्रशासन इस पूरे अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं का विस्तार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि विकास की मुख्यधारा से छूटे इन क्षेत्रों को स्थाई रूप से मजबूत किया जा सके। इस सकारात्मक बदलाव से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और ग्रामीणों का मानना है कि इस सुंदर भवन के बनने से न सिर्फ बच्चों की रोजाना उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक माहौल भी तैयार होगा। कल तक जहां डर और सन्नाटा था, वहां अब पक्के स्कूल की ये दीवारें इन आदिवासी बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयार हैं। सुकमा का यह सुदूर अंचल अब साबित कर रहा है कि बंदूक की ताकत पर शिक्षा और विकास का जुजियारा हमेशा भारी पड़ता है।

कोण्डागांव में आयोजित हुई तेजस स्टार्टअप कार्यशाला

युवाओं, उद्यमियों और विद्यार्थियों को स्टार्टअप, फंडिंग एवं नवाचार की दी गई जानकारी

कोण्डागांव। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोण्डागांव द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ऑडिटोरियम, कोण्डागांव में तेजस स्टार्टअप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना, जिला पंचायत सदस्य नंदलाल राठौर, यशोदा कश्यप एवं प्रेम सिंह नाग भी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य जिले के उद्यमियों, उद्योगपतियों, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों तथा स्वरोजगार और नवाचार के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को स्टार्टअप से संबंधित नवीनतम जानकारी, अवसरों एवं शासकीय योजनाओं से अवगत कराना था। कार्यशाला में स्टार्टअप विशेषज्ञों एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों ने नया व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रिया, स्टार्टअप पंजीयन, विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता, व्यवसाय विस्तार तथा उद्यमिता विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों को नवाचार आधारित उद्यम स्थापित करने, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने तथा अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस दौरान कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए युवाओं ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने आइडिया साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने कहा कि शासन युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना सहित कई योजनाएं संचालित कर रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि, कला एवं हुनर को पहचानकर उसे उद्यम के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार-प्रसार का प्रभावी माध्यम बन चुका है, जिसका उपयोग कर युवा अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। कलेक्टर ने युवाओं से संवाद करते हुए उनके स्टार्टअप संबंधी विचारों और नवाचारपूर्ण अवधारणाओं को जाना तथा प्रेरणादायी उदाहरणों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार अपनाकर सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।

43 शिक्षकों से 12 करोड़ की लोन ठगी का हुआ भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

फरसगांव। फरसगांव और केशकाल पुलिस ने शिक्षकों से करोड़ों रुपये की लोन ठगी करने वाले अंतर्जिला संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लगभग तीन माह तक चली गहन जांच, बैंक खातों के विश्लेषण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह पर 43 शिक्षकों को मल्टीपल बैंक पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवशंकर दास, दिलीप कुमार सोनी, वीरेन्द्र तिर्की, श्यामसुन्दर जांगड़े तथा अंशुमान सिंह शामिल हैं। इनमें से एक आरोपी को अंबिकापुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया।

40% रकम देकर 60% खुद हड़पते थे आरोपी: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिक्षकों को एक साथ कई बैंकों से पर्सनल लोन स्वीकृत कराने का झांसा देते थे। लोन स्वीकृत होने के बाद कुल राशि का लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों को देकर शेष 60 प्रतिशत अपने एवं अपने सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। इतना ही नहीं, आरोपी यह भरोसा भी दिलाते थे कि अगले दो से तीन वर्षों तक लोन की पूरी ईएमआई वे स्वयं जमा करेंगे। इसी लालच में फरसगांव, केशकाल, बड़ेडोंगर, धनोरा और विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के 43 शिक्षक इनके जाल में फंस गए।

तीन माह की जांच के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा के निर्देशन में एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय एवं एसडीओपी केशकाल अरुण नेताम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर एक ही समय में अलग-अलग बैंकों से कई पर्सनल लोन स्वीकृत कराए। पुलिस को बैंक कर्मचारियों एवं लोन एजेंटों की संभावित मिलीभगत के भी संकेत मिले हैं।

स्पेशल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं आधिकारिक प्रकरणों का निराकरण हेतु बैठक आयोजित

कोंडागांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली/छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय की अध्यक्षता में आगामी 18 जुलाई को आयोजित स्पेशल लोक अदालत (धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 चेक बाउंस प्रकरण) के सफल आयोजन तथा अधिकाधित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से मध्यस्थता केन्द्र में कोंडागांव जिले के समस्त बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्पेशल लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित, सरल एवं आपसी सहमति के आधार पर निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों का समय, धन एवं श्रम की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आती है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत के लाभों से अवगत कराते हुए आधिकारिक प्रकरण समझौते के लिए प्रस्तुत करें। साथ ही सभी बैंक अधिकारियों को स्पेशल लोक अदालत को जनहित एवं न्याय हित की दृष्टि से सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। साथ ही बैठक में बैंक कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने बैंक से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर अधिकाधिक प्रकरण स्पेशल लोक अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित खाताधारकों, शिकायतकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से पूर्व संपर्क स्थापित कर उन्हें लोक अदालत के लाभों की जानकारी दें तथा आपसी समझौते के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र निराकरण हो सके। साथ ही यह भी कहा कि बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी न्यायालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध कराएं।

ग्राम पंचायत जोरा के मौहारभांठा प्राथमिक शाला के प्रांगण व शौचालय में जलभराव, बच्चों को मंडराने लगा खतरा

बिलाईगढ़ विधानसभा के कई स्कूल की छत जर्जर तो कहीं शौचालय नही, किचन शेड जर्जर, शिक्षक की कमी जैसी समस्या है बनी

भटगांव। स्कूल सत् प्रारंभ हो चुके हैं और सभी जगहों के स्कूलों में जोर शोर से शाला प्रवेश उत्सव सभी जगहो के स्कूलों में मनाई गयी और स्कूल में बच्चों का स्वागत भी बड़े ही उत्साह के साथ किया गया लेकिन आज भी स्कूल जाने वाले बच्चो को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के माता पिता का सपना रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने और बच्चों को भी ये उम्मीद रहता है कि हम स्कूल जाकर हमें अच्छी शिक्षा मिले लेकिन वही बच्चो को स्कूल जाने मे और शिक्षा अध्ययन करने में कष्ट हो तो क्या होगा।

बरसात के दिनों में स्कूलों की स्थिति बद से बत्तर

आपको बता दें कि 16 जून स्कूल सत्र प्रारंभ हो गया है और बच्चों को भी स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम स्कूल खुले तो पढ़ने लिखने जाये और पढ़ लिख कर अपने स्कूल, माता पिता और नगर व गांव का नाम रोशन करें लेकिन स्कूल खुले अब काफी दिन हो गया और बरसात का भी दिन है लेकिन बरसात के दिनों में स्कूलों की स्थिति जहां छोटे-छोटे बच्चो को पढ़ने लिखने और आने जाने में में होने वाली समस्या, जहां बिलाईगढ़ विधानसभा के कई स्कूल है जहां की स्कूल की छत जर्जर है तो कहीं शौचालय नही, किचन शेड जर्जर, शिक्षक की कमी जैसी और भी कई प्रकार की समस्या सामने आता है पर इस पर शिक्षा विभाग द्वारा समाधान नहीं कर पाते और स्कूल शिक्षा सत्र समाप्त हो जाते हैं। पर स्कूलो की स्थिति पढ़ने वाले बच्चों की समस्या ज्यों का त्यों बना रहता है। जिस पर शिक्षा विभाग चुप्पी साधे रह जाता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की सुविधा व अच्छी शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल का संचालन करवाया जा रहा है पर जिला स्तर के अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलो की हो रही परेशानी को दूर करने के लिए ध्यान नहीं दे रही है जिससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूली बच्चों में परेशानिया बनी रहती है। दरअसल हम बात कर रहे है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के ग्राम पंचायत जोरा के पास स्थित मौहारभांठा प्राथमिक शाला के प्रांगण व शौचालय की जहां स्कूल प्रांगण में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है।

मौहारभांठा स्कूल में पानी निकासी की नहीं व्यवस्था

जहां मौहारभांठा स्कूल प्रांगण में पानी किसी तालाब से कम नहीं लग रहे हैं। पिछले चार दिनों से हुई बारिश ने बच्चों के जान जोखिम में डाल दिए हैं। वहीं पढ़ाई करने के लिए बच्चे जद्दो जहद कर रहे है। जहां शाला परिसर में भरी पानी में सर्प और बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु भी निकल रहे है। साथ ही साथ स्थाई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़े हादसे होने की संभावना बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल भी उठना लाजमी है कि इस हालत के जिम्मेदार कौन है? यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ यदि बड़ा ह्रादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। बहरहाल स्कूल प्रांगण और शौचालय में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए स्थाई पानी निकासी की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। जहां अब देखना होगा कि पंचायत और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कब तक पानी निकासी की व्यवस्था बना पाते हैं या नहीं या यूं ही बच्चे स्कूल प्रांगण में भरे पानी को पार कर स्कूल जाते रहेंगे जो एक सोचनीय विषय बना हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को रेलमंत्री राजभाषा पुरस्कार

बिलासपुर। रेलवे में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं उससे उच्चतर स्तर

के अधिकारियों को रेल मंत्री राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पदक उन उच्च अधिकारियों के प्रदान किये जाते हैं जिनका अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान रहा है और जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही वे स्वयं भी हिंदी में कार्य करते हैं । श्री बिजय कुमार, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा वर्ष 2024 में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (विपणन) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के पद पर रहते हुए राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किया गया है । इसके लिए उन्हें रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा रेलमंत्री राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें नकद पुरस्कार सहित प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड से सम्मानित किया जाएगा । निश्चय ही यह पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के लिए एक गौरव का विषय है ।

श्री गंगानगर-पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी -3 कोच की सुविधा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाड़ी 20471/20472 श्री गंगानगरङ्कपुरीङ्कश्री गंगानगर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है 7 इस व्यवस्था के तहत श्री गंगानगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 20471 श्री गंगानगरङ्कपुरी एक्सप्रेस में दिनांक 12 से 26 जुलाई 2026 तक तथा पुरी से चलने वाली गाड़ी संख्या 20472 पुरी श्री गंगानगर एक्सप्रेस में दिनांक 15 से 29 जुलाई 2026 तक एक अतिरिक्त एसी थ्री कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

जमीन और पानी निकासी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों से मारपीट में दर्जनभर घायल

बिलासपुर। जिले के कोनी थाना क्षेत्र के सेमरताल भदोरिया खार बरपाली गांव में जमीन और पानी निकासी के पुराने विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी-डंडे चले, जिससे महिला और पुरुषों सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस के अनुसार, एक पक्ष के हरवंश राजू लोनिया ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पड़ोसी हरीशानंद, परमानंद, संतोषानंद और उनके बेटों ने सड़क पर मिट्टी डालकर पानी निकासी का रास्ता बंद कर दिया था। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर उनके घर में घुसकर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के हरीशानंद लोनिया ने भी कोनी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि वह अपने आंगन में मौजूद थे, तभी पड़ोसी राजेश, राजू, भानू और बैसाखूराम लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में उनके परिवार के कई लोगों को चोटें आई हैं।

मेरा बस चले तो पूरी विधानसभा को शराबमुक्त कर दूं' : विधायक शकुंतला पोर्ते का बयान वायरल

सूरजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह नशामुक्त समाज और शराबबंदी को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहती नजर आ रही हैं कि मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को शराब-मुक्त कर दूं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पोर्ते ने कहा कि किसी व्यक्ति पर शराब नहीं पीने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन समाज और परिवार के हित में लोगों को स्वयं आगे आकर नशे से दूरी बनानी चाहिए। उन्होंने लोगों से शराब और अन्य बुरी आदतों को छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति भी गलत रास्ते पर जाने से बचता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।

18 जुलाई को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का महाअभियान, बिलासपुर में लगेंगे लाखों पौधे

कलेक्टर अग्रवाल ने तैयारियों की समीक्षा की,बोले: पौधे कम लगाएं, लेकिन उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता हो.....

बिलासपुर। जिले में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय ग्रामीणों, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संस्थाओं तथा उद्योगों के सहयोग से इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना आसान है, लेकिन उन्हें बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में करीब 14.50 लाख पौधे उपलब्ध हैं। इनमें लगभग 12.25 लाख पौधे वन विभाग तथा 2.25 लाख पौधे उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार रखे हुए हैं। उद्यान विभाग द्वारा करीब 75 हजार पौधे इच्छुक नागरिकों को नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सरकंडा, वेदपरसदा (मस्तूरी), बहतराई (तखतपुर) और करगीकला (कोटा) स्थित नर्सरियों से पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष अभियान में मुख्य रूप से फलदार एवं छायादार पौधों के रोपण पर जोर दिया जाएगा। बड़े आकार के पौधे लगाए जायेंगे।कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष ब्लॉक प्लांटेशन की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पौधरोपण के बाद पौधों की जिम्मेदारी बिहान की महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी जाए, ताकि

भविष्य में फल उत्पादन से उन्हें अतिरिक्त आय का लाभ भी मिल सके। उन्होंने ऐसे पौधों के रोपण पर बल दिया, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने में भी सहायक हों। बैठक में कलेक्टर ने बताया गया कि 18 जुलाई को जिलेभर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अभियान में स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और आम नागरिक भी सहभागी होंगे। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय कार्यालयों तथा शासकीय भूमि पर पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदने सहित अन्य तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। कलेक्टर ने प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल गांव विकसित करने के निर्देश उद्यान विभाग को दिए। इन गांवों को किसी एक विशेष फलदार प्रजाति, जैसे आम, अमरूद या मुनगा के आधार पर विकसित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ये गांव फल उत्पादन के साथ ग्रामीणों की आय बढ़ाने के मॉडल बन सकें। उन्होंने उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने अभियान में सहयोग का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि उद्योगों के आसपास उपलब्ध भूमि पर भी पौधरोपण किया जाए, जिससे उनकी नियमित देखरेख और संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके।बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल, डीएफओ नीरज सहित विभिन्न शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने दो तहसीलों का किया गया औचक निरीक्षण

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर एवं सकरी तहसीलों का निरीक्षण कर राजस्व कार्यों की प्रगति और अभिलेखों के संधारण का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व प्रकरणों की फाइलों का अवलोकन कर उनके निराकरण की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में नियमित एवं शीघ्र-शीघ्र पेशियां निर्धारित कर प्राथमिकता के साथ उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न

करना पड़े।कलेक्टर श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से नक्शा बटांकन और सीमांकन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्शा बटांकन लंबित रहने से भूमि संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नागरिकों को विभिन्न शासकीय कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कार्य में तेजी लाते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।उन्होंने तहसीलों में रखे जाने वाले राजस्व अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव पर भी जोर दिया और कहा कि अभिलेख सुरक्षित, अद्यतन एवं व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसील कार्यालय पहुंचे राजस्व प्रकरणों के पक्षकारों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

वीबी-जी-रामजी योजना से श्रमिकों को मिली बड़ी राहत

सूरजपुर संवाददाता। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण श्रमिकों के हित में संचालित वीबी-जी-रामजी योजना जिले के श्रमिक परिवारों के लिए राहत और संबल का माध्यम बन रही है। योजना के तहत दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि तथा 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की व्यवस्था से श्रमिकों में उत्साह का वातावरण है। इससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम ऊँचडीह, पोस्ट बसदेई सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रमिकों ने योजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री टुकेंद्र प्रसाद, श्री तोजेश राजवाड़े, श्री प्रभुनारायण, श्री भूपेंद्र प्रसाद, श्रीमती महेश्वरी, श्रीमती

लीलावती, श्रीमती नीरा बाई, श्रीमती कामेश्वरी, श्रीमती नरबदिया, श्रीमती विमला, श्री रामावतार, श्रीमती फूलकुंवर, श्रीमती देवकुमारी, श्री शिवप्रसाद और श्री भागीरथी सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि पहले उन्हें 100 दिनों तक रोजगार मिलता था, जबकि अब 125 दिनों तक रोजगार मिलने की व्यवस्था से उनकी आय के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलने से परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत होगी।श्रमिकों ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अतिरिक्त आय से बच्चों की पढ़ाई, राशन, स्वास्थ्य और अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भू-जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन को लेकर विशेषज्ञों ने साझा किए महत्वपूर्ण सुझाव...

बिलासपुर। दिनाँक 10 जुलाई 2026। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर में "Ground Water Regulation and Control" विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण नई दिल्ली तथा केंद्रीय भू-जल बोर्ड उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भू-जल संरक्षण, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा इससे जुड़े नियामकीय प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण) श्री सी. जयदेव विशिष्ट अतिथि के

रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों एवं इकाइयों से आए अधिकारी-कर्मचारी तथा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्री सी. जयदेव ने कहा कि जल संरक्षण केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और जल का वैज्ञानिक प्रबंधन समय की आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए नियमों, बेहतर कार्यप्रणालियों और जल संरक्षण के प्रभावी उपायों को समझने का अवसर मिलता है। दो दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं इकाइयों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने भू-जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण (Recharge), उद्योगों में जल के बेहतर उपयोग तथा भू-जल से जुड़े नियामकीय प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी साझा की। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (CGWA), नई दिल्ली से डॉ. प्रबीर के. नाइक (Regional Director), श्री उद्देश्य कुमार (Scientist-C) एवं सुश्री एच. वी. सोफिया के (Scientist-C) तथा केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB), उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर से डॉ. भूषण आर. लामसोगे (Regional Director), श्री सिद्धांत कुमार साहू (Scientist-C), सुश्री सायली उमेश तेंबूर्णे (Scientist-C) एवं श्री प्रमोद साहू (Scientist-C) ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।

शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर में नवजीवन नशा विरोधी जन जागरूकता महाअभियान का आयोजन

- नशे को ना कहें, जीवन को हां कहें'' के संदेश के साथ छात्र-छात्राओं ने ली नशा मुक्त भारत की शपथ
- राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं थाना चांदनी बिहारपुर के संयुक्त सहयोग से हुआ प्रेरक कार्यक्रम

सूरजपुर संवाददाता/ नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में शासकीय नवीन महाविद्यालय, चांदनी बिहारपुर में ्नवजीवनष् नशा विरोधी जन जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत 'नशे को ना कहें, जीवन को हां कहें' विषय पर एक प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं स्थानीय थाना चांदनी बिहारपुर के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय एवं थाने के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रभारी श्री रंजीत कुमार सातपुते की उपस्थिति तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी श्री धीरेंद्र कुमार जायसवाल एवं सहायक उप निरीक्षक श्री क्षेत्रपाल सिंह के नेतृत्व एवं संचालन में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री धीरेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा उपस्थित समस्त विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नशे से दूर रहने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनने की शपथ दिलाई गई। थाना सहायक प्रभारी श्री क्षेत्रपाल सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने की समझाइश दी और आह्वान किया कि वे अपने घर, आस-पड़ोस, मोहल्ला, टोला एवं बिहारपुर क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं जागरूकता के माध्यम से अपने गांव, घर, मोहल्ला एवं क्षेत्र में नशा मुक्ति की पहल कर भारत को नशा मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में थाना चांदनी बिहारपुर से श्री भुवनेश्वर, श्री मनजीत एवं उनके सहयोगी, विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री अच्छेबर गुप्ता तथा महाविद्यालय परिवार से श्री संदीप मिंज, सुश्री लक्ष्मी साहू सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अनूपपुर कटनी रेलखंड में विकास को मिल रही है नई गति

- तीसरी लाइन, 110 किमी/घंटा गति, अमृत भारत स्टेशन योजना एवं बेहतर यात्री सुविधाओं से रेल संचालन हुआ है और अधिक सुरक्षित एवं सुगम

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अनूपपुर (APR)-कटनी रेलखंड में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के विभिन्न कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। तीसरी लाइन, गति वृद्धि, अमृत भारत स्टेशन योजना, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा संरक्षा संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण रेलखंड की परिचालन क्षमता, सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तीसरी लाइन से बढ़ी परिचालन क्षमता अनूपपुर-कटनी रेलखंड पर 165.52 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन के चालू होने से रेल परिचालन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध हुआ है। अतिरिक्त लाइन उपलब्ध होने से यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन बेहतर ढंग से किया जा रहा है। इससे लाइन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा ट्रेनों के संचालन में गतिशीलता आई है। रेलखंड में गति वृद्धि (Speed Raising) के अंतर्गत अनूपपुर (APR) सिंहपुर (SNGP), लोरहा (LOA) विलायतकलां (VYK) तथा रुपौंद (RPD) न्यू कटनी जंक्शन (NKJ) खंडों पर 110 किमी/घंटा की गति सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। वहीं सिंहपुर (SNGP) लोरहा (LOA) तथा

विलायतकलां (VYK) रुपौंद (RPD) खंड पर भी 110 किमी/घंटा गति लागू करने के लिए आवश्यक कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। गति वृद्धि से ट्रेनों के समयपालन में और सुधार होगा तथा रेल परिचालन की समग्र दक्षता और क्षमता में वृद्धि होगी। रेलखंड के प्रमुख स्टेशन अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत व्यापक विकास कार्य प्रगति पर है जो कि पूर्णता की ओर अग्रसर है । स्टेशन भवनों का आधुनिकीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, बेहतर पहुंच मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार तथा स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा। इस खंड की बढ़ी हुई क्षमता के कारण विभिन्न स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के संचालन एवं ठहराव में भी सुधार किया जा रहा है। इस सेक्शन की क्षमता बढ़ने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस का अनूपपुर, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस का नौरोजाबाद व रुपौंद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया गया है। जिससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और छात्र-छात्राओं को यात्रा करने में अभूतपूर्व सुविधा हो रही है।

शरीर के टाइप के हिसाब से करें जींस का चयन

आज के फैशन ट्रेंड में जींस हर उम्र के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सही जींस चुनना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर लोग सिर्फ डिजाइन या ट्रेंड देखकर जींस खरीद लेते हैं, जो उनके शरीर के टाइप पर फिट नहीं बैठती और लुक खराब कर देती है। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है और उसी के हिसाब से जींस का चयन करना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही फिटिंग की जींस न केवल आपके लुक को स्टाइलिश बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। आजकल मार्केट में स्किनी, स्ट्रेट, बूटकट और रिलैक्स्ड फिट जैसी कई वैरायटी मौजूद हैं। अगर आप अपने बॉडी शेप को समझकर जींस चुनते हैं, तो आपका ओवरऑल लुक और भी आकर्षक दिखता है। यही वजह है कि फैशन की दुनिया में "बॉडी टाइप बेस्ड ड्रेसिंग" एक नया ट्रेंड बन गया है।

1. स्लिम बॉडी टाइप

अगर आपका शरीर स्लिम है, तो आपको ऐसी जींस चुननी चाहिए जो आपके फिगर को थोड़ा डिफाइन और बैलेंस दिखाए। स्किनी फिट या स्लिम फिट जींस इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है क्योंकि यह पैरों को शेप देकर लुक को स्मार्ट बनाती है। हल्के स्ट्रेच वाली डेनिम भी बेहतर रहती है ताकि मूवमेंट आरामदायक रहे। बहुत ज्यादा ढीली जींस पहनने से लुक और पतला दिख सकता है, इसलिए फिटेड स्टाइल ज्यादा उपयुक्त माना जाता है।

2. कर्वी बॉडी टाइप

कर्वी बॉडी टाइप के लिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो कमर और हिप्स को सही तरह से सपोर्ट दे। हाई-वेस्ट स्ट्रेट फिट या बूटकट जींस इस बॉडी शेप पर सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह शरीर के कर्व्स को बैलेंस करती है और एक स्मूथ सिल्हूट देती है। स्ट्रेच डेनिम वाली जींस पहनने से आराम भी मिलता है और फिटिंग भी बेहतर रहती है। बहुत टाइट स्किनी जींस से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनकंफर्टेबल फील हो सकता है।

3. एथलेटिक बॉडी टाइप

एथलेटिक बॉडी में शरीर फिट और मस्कुलर होता है, इसलिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो बॉडी के साथ बैलेंस बनाए रखे। रिलैक्स्ड फिट या टेपर जींस इस बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट रहती है। यह लुक को न तो बहुत टाइट बनाती है और न ही बहुत ढीला, जिससे एक स्मार्ट और क्लीन अपीयरेंस मिलता है। हल्के डार्क शेड्स की डेनिम भी इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है और स्टाइल को और बेहतर बनाती है।

4. रेक्टेंगल बॉडी टाइप

इस बॉडी शेप में कमर कम डिफाइंड होती है और शरीर लगभग सीधा दिखता है। ऐसे में फ्लेयर्ड या हाई-वेस्ट जींस पहनने से कमर को शेप मिलता है और एक कर्वी इफेक्ट क्रिएट होता है। यह स्टाइल शरीर को ज्यादा बैलेंस्ड और स्टाइलिश दिखाता है। हल्की बेल बॉटम या वाइड लेग जींस भी इस बॉडी टाइप के लिए अच्छी रहती है क्योंकि यह लुक में डाइमेंशन जोड़ती है।

भूलकर भी घर में न लगाएं ये पौधे

घर में लगे पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होते, ये हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित भी करते हैं। कई लोग हरियाली बढ़ाने के लिए तरह-तरह के पौधे लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर पौधा घर के लिए शुभ नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी माने जाते हैं, जो अनजाने में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और घर के माहौल को प्रभावित कर देते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे परिवार में तनाव, रुकावट और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी के साथ ही पौधों का चयन किया जाए। आइए जानते हैं किन पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए।

बोन्साई पौधा

बोन्साई देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन इसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि यह पौधा जीवन में प्रगति को सीमित कर देता है और करियर की गति को धीमा कर सकता है।

इमली का पेड़

इमली का पौधा या पेड़ घर के भीतर या आसपास लगाना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिससे घर में परेशानी बढ़ सकती है।

सूखे या मुरझाए पौधे

घर में सूखे या खराब हो चुके पौधों को रखना भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे पौधे नकारात्मकता का संकेत होते हैं और जीवन में रुकावटें ला सकते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए।

दूध निकलने वाले पौधे

ऐसे पौधे जिनसे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, उन्हें भी घर में लगाने से बचना चाहिए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ये पौधे आर्थिक तंगी और कर्ज बढ़ने का कारण बन सकते हैं।

घर में कौन से पौधे लगाना शुभ होता है?

वास्तु के अनुसार, कुछ पौधे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे तुलसी, मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और शमी का पौधा। ये पौधे घर में सुख-शांति और खुशहाली लाने में सहायक माने जाते हैं।

काटने के कितने देर बाद खराब हो जाते हैं फल?

आप भी फलों को काटकर फ्रिज में रखते हैं? कई लोग ऐसा करते हैं कि फलों को काटकर फ्रिज में स्टोर करते हैं, खासकर पपीता या तरबूज जैसे फल। हमें लगता है कि फ्रिज में रखने से ये ताजे और ठंडे रहेंगे, लेकिन क्या आपकी यह आदत आपकी सेहत के लिए सही है? आइए जानते हैं कि क्या फ्रिज में कटे हुए फलों को रखना सुरक्षित है और कितनी देर के अंदर कटे हुए फल खा लेने चाहिए।

क्यों खतरनाक हो सकते हैं कटे फल?

दरअसल, जैसे ही हम किसी फल को काटते हैं, वह बाहर की हवा, नमी और कीटाणुओं के संपर्क में आने लगते हैं। इसलिए कटे हुए फल पर साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई। कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रिज इन बैक्टीरिया के पनपने की गति को धीमा तो करता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करता। साथ ही, हवा के संपर्क में आने से फलों में ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है, जिससे विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व कम होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सेब या केला काटने के कुछ देर बाद भूरा होने लगता है, यह इसी प्रक्रिया का संकेत है।

कितने घंटे तक ठीक रहते हैं कटे फल?

फलों की ताजगी और सुरक्षा उनके प्रकार और तापमान पर निर्भर करती है। अगर कटे हुए फल बाहर रखे हैं, तो उन्हें 4 से 6 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अगर फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियर से नीचे है, तो कटे हुए ज्यादातर फल 24 घंटे तक सुरक्षित माने जाते हैं।

स्टोर करने के दौरान होने वाली आम गलतियां

अक्सर लोग फलों को प्लेट में खुला छोड़ देते हैं या उन्हें एल्युमिनियम फॉयल में ढीला लपेटकर रख देते हैं। बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से तापमान में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे फलों की गुणवत्ता गिरती है। हर बार जब आप कंटेनर खोलते हैं, तो दूषित हवा अंदर जाती है, जो फल को खराब करने की प्रक्रिया तेज कर देती है।

तरबूज, खरबूजा, पपीता और अनानास जैसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वे जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि इनमें नमी के कारण बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं।

सुरक्षित रखने के सही तरीके

अगर आपको फल काटकर रखना ही है, तो इन नियमों का पालन करें-

एयरटाइट कंटेनर- फलों को हमेशा कांच के एयरटाइट कंटेनर में रखें। यह हवा के संपर्क को कम करता है और गंध को फल में जाने से रोकता है।

स्वच्छता- फल काटने से पहले हाथ, चाकू और कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह धोएं। गंदे चाकू से फल काटने पर बैक्टीरिया तुरंत अंदर तक पहुंच जाते हैं।

रेफ्रिजरेशन- फल काटने के तुरंत बाद उन्हें फ्रिज में रख दें।

खराब फल की पहचान कैसे करें?

कभी-कभी फल 24 घंटे के भीतर भी खराब हो सकते हैं। इन संकेतों पर ध्यान दें- अगर फल से फर्मेंटेशन जैसी खट्टी गंध आ रही है। अगर फल चिपचिपा हो गया है या बहुत ज्यादा पानी छोड़ रहा है। अगर फल का रंग बहुत गहरा या काला पड़ गया है।

आज का राशिफल

मेष राशि - आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक मजबूती का रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित है। प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। करियर में प्रमोशन के योग हैं और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। बिजनेस में नई योजनाओं पर अमल करना लाभदायक रहेगा, जिससे आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा। लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में सुखद स्थिरता आएगी।

वृषभ राशि - आपके लिए पराक्रम और संवाद कौशल में सफलता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि में सूर्य-बुध की उपस्थिति करियर में आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगी। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप तरक्की करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ छोटी यात्रा के योग हैं।

मिथुन राशि - आपके लिए धन संचय और पारिवारिक खुशियों का है, क्योंकि आपकी राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। आपकी राशि में गुरु और शुक्र की युति करियर में असाधारण प्रगति और पदोन्नति के द्वार खोलेगी। बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

कर्क राशि - आपकी राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में विराजमान हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और महत्वपूर्ण निर्णयों में सफलता मिलेगी। व्यापार में तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक लाभ संतोषजनक रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी।

सिंह राशि - आपके लिए खर्चों और बाहरी संपर्कों पर ध्यान देने का है, क्योंकि आपकी राशि के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हैं। करियर के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव संभव है। बिजनेस में कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचें, आर्थिक हानि के संकेत हैं। विरोधियों की प्रतिस्पर्धा आपको नई रणनीतियां बनाने पर मजबूर करेगी।

कन्या राशि - आपके लिए लाभ और खुशियों की नई किरण लेकर आएगा, क्योंकि आपकी राशि के एकादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे और आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। बिजनेस में बड़े लाभ के योग हैं और नए संपर्कों से आय बढ़ेगी। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ आप किसी सुखद भविष्य की योजना बनाएंगे। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा।

तुला राशि-आपके लिए करियर में मान-सम्मान और अधिकार प्राप्ति का है, क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। नौकरी में आपके काम की गुणवत्ता आपको प्रमोशन की ओर ले जा सकती है। बिजनेस में स्थिरता आएगी और पुराने निवेशों से आर्थिक लाभ होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि - आपके लिए भाग्य की उन्नति और नई संभावनाओं का रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के नवम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में है। करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। बिजनेस में नई शुरुआत करना लाभदायक रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और आप पार्टनर के साथ गहरा लगाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं।

धनु राशि- आपके लिए धैर्य और संयम बरतने का है, क्योंकि आपकी राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। बिजनेस में उधारी के लेनदेन से बचें, आर्थिक हानि की संभावना है। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।

मकर राशि - आपके लिए साझेदारी और मधुर रिश्तों का होगा, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। बिजनेस में नए अनुबंध हो सकते हैं, जो भविष्य में तरक्की दिलाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए निवेश की योजना बनेगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में आकर्षण बना रहेगा।

कुंभ राशि- आपके लिए अनुशासन और विरोधियों पर विजय पाने का है, क्योंकि आपकी राशि के छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। करियर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में आपके काम की बारीकियों पर ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन सफलता निश्चित है।

मीन राशि- आपके लिए रचनात्मकता और खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित हैं। करियर में आपके नवाचारों की सराहना होगी और नई शुरुआत के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे। बिजनेस में प्रगति होगी और निवेश से अच्छा लाभ होने के योग हैं। लव लाइफ में प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और पार्टनर के साथ रिश्ते और गहरे होंगे।

आलू उबालते वक्त कुकर में डाल दीजिए ये चीजें

छीलने में नहीं होगी परेशानी

हमारे यहां खाने-पीने की बात हो और आलू का जिक्र न हो, ऐसा नामुमकिन है। अधिकतर लोग आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसे कई तरह की सब्जियों में डाला जाता है और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू से बनी सब्जी, पराठा, टिक्की, चाट, सैंडविच और स्नैक्स लगभग हर घर में पसंद किए जाते हैं। कई बार आलू उबालने के बाद उनका छिलका आसानी से नहीं उतरता या फिर उनका स्वाद फीका लगने लगता है। अगर आलू उबालते समय कुकर में कुछ खास चीजें डाल दी जाएं, तो आलू न सिर्फ अच्छे से उबलते हैं, बल्कि उनका स्वाद और टेक्सचर भी बेहतर हो सकता है।

नमक डालने से आलू बनेंगे टेस्टी

आलू उबालते समय पानी में थोड़ा नमक डालना एक बेहद आसान, लेकिन असरदार तरीका माना जाता है। नमक उबलते पानी के साथ आलू के अंदर तक पहुंच सकता है, जिससे आलू हल्के नमकीन और ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। नमक डालने से आलू का छिलका थोड़ा ढीला हो जाता है, जिससे उसे उतारना आसान हो सकता है। खासकर अगर आलू बड़े आकार के हों, तो यह तरीका काफी काम आ सकता है।

एक चम्मच तेल करेगा कमाल

आलू उबालते समय कुकर में एक छोटा चम्मच तेल डालना भी फायदेमंद माना जाता है। तेल आलू की ऊपरी सतह पर हल्की परत बना सकता है, जिससे उबलने के बाद छिलका आसानी से अलग होने लगता है। तेल डालने से आलू ज्यादा फटते या टूटते नहीं हैं। अगर आप आलू का इस्तेमाल सलाद, चाट या टिक्की जैसी डिश में करना चाहते हैं, जहां आलू का सही आकार बनाए रखना जरूरी होता है, तो यह ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है।

नींबू का रस सुधारेगा स्वाद

कुछ लोग आलू उबालते समय पानी में थोड़ा सा नींबू रस डालते हैं। माना जाता है कि इससे आलू का रंग ज्यादा अच्छा बना रहता है और उबालने के बाद उनका छिलका जल्दी निकल सकता है। नींबू की हल्की खटास आलू के स्वाद को भी थोड़ा बेहतर बना सकती है। खासकर अगर आप उबले आलू से सलाद या स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, तो यह तरीका स्वाद में हल्का ट्विस्ट ला सकता है।

बच्चों की सही ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत जरूरी

बच्चों की सही ग्रोथ और मजबूत इम्यूनिटी के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए, तो कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं। इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है।

विटामिन ए की कमी के लक्षण

विटामिन ए बच्चों की आंखों, इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चे को रात में कम दिखाई देना शुरू हो सकता है। आंखों में खुजली, सूखापन या बार-बार आंखें मलना भी इसका संकेत हो सकता है। ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी भूख भी कम हो सकती है। लंबे समय तक कमी रहने पर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।

विटामिन बी1 की कमी के लक्षण

विटामिन बी1 शरीर को एनर्जी देने और दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है और उसे हर समय थकान महसूस हो सकती है। कई बच्चों की भूख कम हो जाती है और वे पढ़ाई या खेल में ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ मामलों में नसों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर बच्चा अचानक सुस्त रहने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें।

विटामिन बी2 की कमी के लक्षण

विटामिन बी2 की कमी का असर सबसे पहले त्वचा और मुंह पर दिखाई देता है। बच्चे के होंठ बार-बार फटने लगते हैं या मुंह के कोनों पर दरारें पड़ सकती हैं। मुंह में छाले होना, त्वचा पर रैशेज आना और आंखों का लाल या पानी भरा दिखना भी इसके संकेत हैं। इसके अलावा, बच्चे की ग्रोथ धीमी हो सकती है। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें, तो बच्चे की डाइट की जांच करवानी चाहिए।

विटामिन बी6 की कमी के लक्षण

विटामिन बी6 दिमाग, इम्यूनिटी और खून बनाने के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चा जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। त्वचा पर रैशेज, होंठों के आसपास दरारें और बार-बार बीमार पड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या भी हो सकती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। इसलिए संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है।

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण

विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चे की त्वचा पीली दिख सकती है। बच्चा जल्दी थक सकता है और उसकी भूख भी कम हो सकती है। कई बार हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है।

दही खाना सेहत के लिए फायदेमंद

दही भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लोग इसे अलग-अलग तरीके से खाते हैं, किसी को नमकीन दही (रायता या छाछ) पसंद है, तो कोई मीठा दही (चीनी, मिश्री या शहद वाला) खाना पसंद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस स्थिति में कौन-सा दही ज्यादा अच्छा है और किसे कब लेना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं।

नमकीन दही (रायता या छाछ)

कब खाना चाहिए? **दोपहर के भोजन के साथ। मसालेदार या भारी खाने के साथ।**

पाचन के लिए बेहतरीन: यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है और खाना जल्दी पचने में मदद करता है।

शरीर को ठंडा रखती है: नमकीन दही या छाछ शरीर को ठंडा रखती है और लू से बचाने में मदद करती है।

इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस: नमक और मसाले शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखते हैं।

गैस और एसिडिटी में राहत: खासकर भारी या तला-भुना खाने के बाद यह बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए, अगर आपने चावल, बिरयानी, पराठा या मसालेदार सब्जी खाई है, तो नमकीन दही सबसे अच्छा विकल्प है।

मीठा दही कब खाना चाहिए?

सुबह खाली पेट या नाश्ते में। कमजोरी या थकान होने पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

इसके फायदे

मीठा दही शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है। इसमें चीनी या शहद मिलाने से शरीर को तुरंत शक्ति मिलती है। मूड बेहतर करता है: मीठा स्वाद दिमाग को सुकून देता है और स्ट्रेस कम करता है। मीठा दही पेट को ठंडक देता है और हल्की भूख में अच्छा लगता है। जो बच्चे खट्टा दही नहीं खा पाते, उनके लिए मीठा दही बेहतर विकल्प है।

संभागायुक्त ने ली संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

संभाग में किसानों को खरीफफसल के लिए खाद बीज की कमी न हो: संभागायुक्त राठौर

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद बीज की कमी न होने पाएं यह सुनिश्चित किया जाए। संभाग अंतर्गत सभी जिलों में उपलब्ध खाद एवं बीज का वितरण किसानों को समय पर किया जाए। संभाग आयुक्त राठौर ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक कृषि से संभाग अंतर्गत खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए उक्त बातें कही। संयुक्त संचालक कृषि ने अवगत कराया कि संभाग में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। उपलब्धता के आधार पर जिलों में कृषि विभाग के अमले द्वारा वितरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभाग के जिलों में लक्ष्य के मुताबिक यूरिया 92 प्रतिशत, डीएपी 40 प्रतिशत, एसएसपी 114 प्रतिशत, एमओपी 98 प्रतिशत एवं एनपीके 88 प्रतिशत उपलब्ध है। इसी प्रकार यूरिया 63 प्रतिशत, डीएपी 30 प्रतिशत, एसएसपी 74 प्रतिशत, एमओपी 63 प्रतिशत एवं एनपीके 66 प्रतिशत सहकारी एवं निजी भंडारण के

माध्यम से किसानों को वितरित की जा चुकी है। संभाग अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला एवं कबीरधाम जिला अंतर्गत भण्डारित 101926 बॉटल नैनो यूरिया में से 61736 बॉटल नैनो यूरिया वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार 83477 भण्डारित नैनो डीएपी में से 48322 बॉटल नैनो डीएपी का वितरण किसानों को हो चुका है। संभाग के जिलों में मांग के विरूद्ध 108597 क्वि. विभिन्न किस्म के खरीफ बीजों का भण्डारण किया गया है। जिसमें से 98069 क्वि. बीजा का वितरण किसानों को किया जा चुका है।

संभाग आयुक्त राठौर ने कृषक प्रशिक्षण पर जोर देते हुए निर्धारित कार्ययोजना के मुताबिक कृषकों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही चालू शिक्षा सत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष जोर देने तथा युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अब तक पद ग्रहण न करने वाले शिक्षकों पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया। संभाग आयुक्त ने नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता पर जोर देते हुए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम-रैली आदि आयोजित करने कहा। उन्होंने उक्त कार्यक्रमों में समाज के अन्य वर्ग को भी भागीदारी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों संबंधित शिकायत व जानकारी साझा करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई टोल फ्री नं. 1933 सभी स्कूल, कॉलेजों के प्रवेश द्वारों पर वॉल राइटिंग कराई जाए। संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी द्वारा निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने तथा आरईएस द्वारा गांवों में महिला सदन का निर्माण गांव के अन्दर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संभाग स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया कि अधीनस्त कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के तहत सहायक ग्रेड-03 पर पदस्थ कर्मचारी को 2 वर्षों के भीतर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) पदुमलाल यादव और उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर एवं समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

11 से 18 तक मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा, निःशुल्क मिलेंगी परिवार नियोजन सेवाएं

दुर्ग। जिले में आगामी 11 से 18 जुलाई 2026 तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का विशेष आयोजन किया जा रहा है। ''जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल'' ध्येय के साथ मनाए जाने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय को गर्भधारण के उचित समय, दो बच्चों के मध्य न्यूनतम 3 साल का सुरक्षित अंतराल रखने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। अभियान के दौरान आम जनता के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और परिवार नियोजन सेवाओं की उपयोगिता बताने के लिए सभी विकासखंडों के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 'सास-बहू सम्मेलन' एवं 'मोर मितान मोर संगवारी चौपाल' जैसे जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े की सफलता के लिए वर्तमान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लक्षित दंपत्तियों से घर-घर संपर्क कर स्वास्थ्य सेवाओं का परामर्श दिया जा रहा है। जिला परिवार कल्याण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. अर्चना चौहान ने बताया कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधन पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा परिवार नियोजन अपनाने वाले लाभार्थियों को आर्थिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिसके तहत महिला नसबंदी के लिए 2,000/- रुपये तथा पुरुष नसबंदी के लिए 3,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त अस्थायी साधनों जैसे- कॉपर-टी, अंतरा इंजेक्शन, गर्भ

नियमों का उल्लघन करने पर मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस हुआ निरस्त

औषधि प्रतिष्ठान नियमों का पालन करते हुए ही कर सकेंगे दवाओं का संग्रहण एवं क्रय-विक्रय

दुर्ग। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स, अहिवारा का औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत 16 जून 2026 को सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झंडेकार एवं औषधि निरीक्षक मती गायत्री पटेल द्वारा मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स, बस स्टैण्ड के सामने, अहिवारा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का औचक निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थान में अन्य औषधियों के साथ अनवांटेड किट/एम.टी.पी. किट का एक नग पाया गया। मौके पर संचालक द्वारा इस संवेदनशील औषधि के संबंध में कोई भी वैध क्रय-विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अवैध रूप से दवा रखने और रिकॉर्ड न होने के कारण फर्म को

विगत 24 जून 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में फर्म द्वारा 30 जून 2026 को कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें संचालक ने उक्त औषधि से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की। फर्म के इस कृत्य को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमों का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन मानते हुए, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झंडेकार द्वारा मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स, अहिवारा को स्वीकृत औषधि लाईसेंस/ अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कार्यवाही के उपरांत, सहायक औषधि नियंत्रक ने जिले में संचालित समस्त औषधि प्रतिष्ठानों के संचालकों को कड़ा संदेश देते हुए आग्रह किया है कि वे एम.टी.पी. किट एवं ऐसी अन्य औषधियां जिनका नशे या अन्य रूप में दुरूपयोग संभव है।

कलेक्टर ने प्रतिदिन 7 घंटे की अवधि पूरी नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

जनप्रतिनिधियों को मिलेगी शासकीय ई-मेल आईडी और सरकारी फाईलों का होगा डिजिटल संचालन

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति में प्रतिदिन 7 घंटे की अवधि पूरी नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र के चयन में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति को आधार बनाने को कहा। कलेक्टर सिंह ने ग्राम पंचायत सचिवों एवं पटवारियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए संबंधित तहसीलदारों से आवश्यक लोकेशन उपलब्ध कराने को कहा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सकों की रोस्टर ड्यूटी ई-ऑफिस के माध्यम से जारी करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जनप्रतिनिधियों को भी शासकीय ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई

जाएगी। नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव तथा पार्षदों को सरकारी ई-मेल आईडी प्रदान कर शासकीय फाइलों का डिजिटल माध्यम से त्वरित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों का आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन एवं ऑनबोर्डिंग कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड अभियान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1300 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, जलजनित रोगों की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग एवं छिड़काव तथा सभी विभागों के लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेजरी अधिकारी को विभागवार बिजली बिल मद में उपलब्ध बजट की सूची तैयार करने को भी कहा। बैठक में पट्टाधारी सर्वे की प्रगति, शासकीय स्कूलों में बायोमेट्रिक अपडेट शिविर, निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के बाद विशेष शिविर आयोजित करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा खाद की उपलब्धता की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने विधानसभा प्रश्नों का समय-सीमा में प्राथमिकता के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन और पीजीएन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आरोपी सोमेश वैष्णव को कलेक्टर ने किया जिलाबदर

सीमावर्ती जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि तक बाहर

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आरोपी सोमेश वैष्णव के आपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी सिंह के आदेशानुसार सोमेश वैष्णव पिता स्वर्गीय गजू दास वैष्णव, उम्र 37 वर्ष, साकिन ग्राम अंजोरा, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग (छ.ग.) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही बदमाश सोमेश को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी की बिना अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक सोमेश वैष्णव वर्ष 2002 से लगातार अपराध की दुनिया में कदम रखे हुए है। आरोपी के विरुद्ध लूट, अपहरण, उदण्डता करना, लोगों को मारना-पीटना, अवैध रूप से हथियार रखकर शराब की बिक्री करना एवं लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने जैसे कई गंभीर अपराध करने की आदत है। आरोपी के विरुद्ध थाना पुलगांव में कई अपराध पंजीबद्ध हैं और समय-समय पर पुलिस द्वारा धारा 151/107, 116(3) एवं धारा 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, फिर भी उसके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया है। आरोपी के इस आतंक से आम जनता और न्यायालय के गवाह भी डरे व भयभीत रहते हैं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। प्रकरण में पुलिस चौकी अंजोरा व थाना पुलगांव से प्राप्त साक्ष्यों तथा अभियोजन के कथनों का बारीकी से अनुशीलन करने के पश्चात, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह ने क्षेत्र में लोक व्यवस्था व शांति बनाए रखने हेतु आरोपी सोमेश वैष्णव के विरुद्ध यह जिलाबदर की सख्त कार्यवाही की है।

माय भारत की जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

दुर्ग। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की पहल माय भारत के अंतर्गत जिला सलाहकार एवं जिला समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में माय भारत योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा, कौशल विकास एवं शासकीय योजनाओं से जोड़ना है। कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में माय भारत पोर्टल पर पंजीयन पर जोर दिया गया। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में माय भारत नोडल अधिकारी एवं कैंपस एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के कार्यक्रम अधिकारियों को विद्यार्थियों का पोर्टल पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन दुर्ग का भी माय भारत पोर्टल पर पंजीयन किया जाएगा, ताकि युवाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं, स्वयंसेवी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर मती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमीत अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ए.पी.गौतम, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, जिला उद्योग सीजीएम बी.आर.निकुंज सहित जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति के सदस्य तथा माय भारत के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने आवश्यक पहल का किया आग्रह

दुर्ग। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे, इसके लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नई दिल्ली में 28 एवं 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चौहान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उपमुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई, जिसके दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आईं, जिसमें सर्वेक्षण के समय कुछ पात्र व्यक्ति पलायन अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो पाया और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका। साथ ही कुछ पात्र परिवारों का सर्वे तो हुआ, लेकिन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो सकी, जिससे ग्राम सभा में उनकी पात्रता प्रदर्शित नहीं हो पाई। शर्मा ने कहा कि इन दोनों कारणों से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे पात्र परिवार आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ के हकदार हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय एवं पहल की जाए।

ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को आवास के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके। अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के प्रति शिवराज सिंह चौहान के निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त किया है।

बरगा-आलीवारा-मुसरा रेल ओवरब्रिज की जांच की मांग, लापरवाही पर हो कार्रवाई : रमन सिंह

- 26 करोड़ के रेल ओवरब्रिज में दरारों पर डॉ. रमन सिंह गंभीर, लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की मांग

राजनांदगाँव। जिले में बरगा, मुसरा और आलिवारा रेलवे ओवरब्रिज की गुणवत्ता का मामला अब गरमा गया है. इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉ. रमन सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर जोन, नागपुर मंडल) अंतर्गत डोंगरगढ़-राजनांदगांव रेलखंड पर ग्राम बरगा, आलीवारा एवं मुसरा के समीप प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था, जिसका लोकार्पण जून 2026 में हुआ था। उन्होंने बताया कि 4 एवं 5 जुलाई को जिले में हुई भारी वर्षा के बाद ओवरब्रिज में लगभग 60 से 70 फीट लंबी तथा 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई दी हैं। इससे पुल की सुरक्षा एवं निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद इस प्रकार की क्षति अत्यंत चिंताजनक है तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों में भी इसे लेकर गहरी चिंता और नाराजगी है। डॉ. सिंह ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए तथा निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, परामर्शदाता और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि ओवरब्रिज का तत्काल सुरक्षा परीक्षण कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

विधायक ललित ने चार वार्डों में 1.72 करोड़ से होने वाले विकास के लिए किया भूमिपूजन

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली में विकास कार्य के लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने भूमिपूजन किया। 1 करोड़ 72 लाख 8 हजार से तालपुरी, रूआबांधा उत्तर, रूआबांधा दक्षिण व रूआबांधा पूर्व में विकास कार्य होंगे। विधायक ललित ने नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भूमिपूजन अवसर पर कहा कि संकल्प पत्र में किए घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार रिसाली को नए कलेवर में आम जनता को समर्पित करेगी। रिसाली की दशा एव दिशा जल्द बदलेगी। विधायक ललित ने कहा कि विकास के नए शोपान के तहत उन्होंने आज वार्ड क्र. 01 से लेकर 04 तक भूमिपूजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश कार्य वही है

जिन्हें जनता ने मांग की है। विकास कार्य के लिए किसी तरह की पैसे की कमी नहीं होगी। भूमिपूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, महापौर परिषद की सदस्य ममता यादव, पार्षद सारिका साहू, सविता ढवस, डॉ. सीमा साहू, सरिता देवांगन, धर्मेन्द्र भगत, शीला नारखेड़े, माया यादव समेत मण्डल अध्यक्ष अनूपम साहू, राजू जंघेल समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे 40 वार्ड में होगा कार्य-भूमिपूजन कार्यक्रम में विधायक ललित ने कहा कि वें पूरे 40 वार्ड में भूमिपूजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। वें शहर के अंतिम छोर तक पहुंचेगें। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि जल्द ही रिसाली निगम क्षेत्र में कॉलेज और नालंदा परिसर का भी निर्माण किया जाएगा।

चार वार्डों में होंगे यह कार्य-वार्ड क्र. 01 तालपुरी में नाली के उपर कव्हर, फेसिंग वर्क, डोम शेड, कव्हर ड्रेन का कार्य 30.22 लाख से पूर्ण किया जाएगा। इसी तरह वार्ड क्र 02 रूआबांधा उत्तर में बाउंड्रीवाल, कम्युनिटी हॉल, पेवर ब्लाक, रोड चैड़ीकरण के लिए शासन ने कुल 69.28 लाख रूपए स्वीकृत की है। वार्ड क्र 03 रूआबांधा दक्षिण में सीसी रोड, कव्हर डेऊन, सड़क चैड़ीकरण के लिए कुल 42.87 लाख रूपए खर्च किए जाऐंगे। इसी तरह वार्ड क्र. 04 रूआबांधा पूर्व में पांच कार्य के लिए 29.71 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। इस राशि से मंच के सामने पेवर ब्लाक, कव्हर ड्रेन आदि विकास कार्य होंगे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com